सुविचार

सज्जन पुरुष बादलों के समान देने के लिए ही कोई वस्तु ग्रहण करते हैं।

कालीदास

दैनिक

रेवांचल टाइम्स

निष्पक्ष, निर्भीक एवं सत्य का प्रवर्तक

Revanchal Times
7509202320
@revanchal_times
revanchaljabalpur@gmail.com
revanchaltimes_

■ वर्ष 3 ■ अंक 79 ■ जबलपुर, सोमवार 16 मार्च 2026 ■ पृष्ठ 8 ■ मूल्य, 01 रुपये ■ RNI. Reg. No MPHIN/2023/90965

असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव नौ से 29 अप्रैल तक, मतगणना चार मई को

नयी दिल्ली,एजेंसी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की रविवार को घोषणा कर दी। ये चुनाव नौ अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच कराये जायेंगे जबकि मतगणना एक साथ चार मई को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यहां एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में बताया कि असम की 126 सीटों, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए एक चरण में चुनाव नौ अप्रैल को कराया जायेगा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर मतदान एक चरण में 23 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव कराया जायेगा। राज्य की कुल 294 सीटों में से पहले चरण में 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए वोट डाले जायेंगे। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो गयी है। असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 16 मार्च को जारी की जायेगी और उसी दिन से नामांकन-पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 मार्च रखी गयी है। उनकी जांच 24 मार्च को होगी और उम्मीदवार 26 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 30 मार्च को जारी की जायेगी और नामांकन पत्र भरने की आखिरी तिथि छह अप्रैल होगी। इनकी जांच सात अप्रैल को की जायेगी तथा उम्मीदवार नौ अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना 30 मार्च को जारी की जायेंगी तथा नामांकन पत्र छह अप्रैल तक भरे जा सकेंगे। इनकी जांच सात अप्रैल को की जायेगी और नाम नौ अप्रैल तक वापस लिये जा सकेंगे। इन सीटों पर मतदान 23 अप्रैल को कराया जायेगा। राज्य की शेष 142 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना दो अप्रैल को जारी की जायेगी और नामांकन पत्र भरने की आखिरी तिथि नौ अप्रैल होगी। नामांकन पत्रों की जांच 10 अप्रैल को की जायेगी तथा नाम 13 अप्रैल तक वापस लिये जा सकेंगे। श्री कुमार ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिये गये हैं और आयोग मतदान-केंद्रो पर मतदाताओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी के भी तरह की हिंसा में लिप्त पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन चुनावों में करीब 25 लाख कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात किये जायेंगे ताकि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराये जा सकें। इनमें 15 लाख मतदान कर्मी, 8.5 लाख सुरक्षा कर्मी, मतदान के लिए 1,444 ऑब्जर्वर, 49 हजार माइक्रो ऑब्जरवर, 40 हजार मतगणना कर्मचारी और 21 हजार सेक्टर ऑफिसर तैनात होगे। मतगणना के लिए 15 हजार माइक्रो ऑब्जर्वर अलग से तैनात होंगे। इन चुनावों में कुल 824 सीटों पर लगभग 17.4 करोड़ मतदाताओं के लिए करीब 2.19 मतदान केंद्र बनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आयोग ने इन राज्यों का दौरा कर वहां के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, राज्यों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद किया है। संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉ. एस.एस. संधु और विवेक जोशी भी उपस्थित थे। श्री कुमार ने कहा, "आयोग प्रत्येक मतदाता का मतदान केंद्र पर स्वागत करने के लिए तैयार है। हम खासकर पहली बार वोट डालने वाले और युवा मतदाताओं से अपील करते हैं कि वे अपने मताधिकार का उत्साह, आत्मसम्मान और विवेक के साथ प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभायें।" उन्होंने बताया कि आयोग ने चुनाव कार्यक्रम तैयार करने से पहले चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर राजनीतिक दलों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों तथा चुनाव अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव इस बार केवल दो चरणों में सम्पन्न कराने के आयोग के निर्णय के बोर में पूछे जाने पर श्री कुमार ने कहा कि आयोग ने इस पर विस्तृत चर्चा की और यह राय बनी कि चुनाव के चरणों की संख्या कम की जाये ताकि यह सभी के लिए सुविधाजनक हो। पश्चिम बंगाल के पिछले चुनाव में हिंसा में लिप्त होने के आरोप में शामिल पुलिस कर्मियों की आगामी चुनाव में ड्यूटी के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या के बारे में उन्होंने कहा कि मौजूदा सूची के अलावा पूरक सूची भी जारी की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार कोलकाता उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाये गये नामों की कानूनी समीक्षा कर रहे न्यायाधीश गण पूरक सूची जारी कर सके हैं।

किम जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चेताते हुए किया मल्टी-रॉकेट टेस्ट का निरीक्षण

प्योंगयांग, एजेंसी। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपनी बेटी के साथ एक शक्तिशाली मल्टी-रॉकेट लॉन्चर परीक्षण का निरीक्षण किया है। सरकारी मीडिया द्वारा रविवार को दी गई जानकारी के अनुसार, किम जोंग उन ने शनिवार को देश के पूर्वी तट पर 12 अति-सटीक 600 मिमी कैलिबर के रॉकेट प्रक्षेपकों के परीक्षण की निगरानी की। इस कदम को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच चल रहे वार्षिक फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास के कड़े जवाब के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि वह इन संयुक्त सैन्य अभ्यासों का मुंहतोड़ जवाब देगा, जिन्हें वह अपने ऊपर आक्रमण की तैयारी और उकसावे के रूप में देखता है। परीक्षण के दौरान किम जोंग उन ने स्पष्ट किया कि यह अभ्यास उनके दुश्मनों को बेचैन करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि इन हथियारों की मारक क्षमता के दायरे में आने वाला प्रतिद्वंद्वी का कोई भी सैन्य बुनियादी ढांचा बच नहीं पाएगा। किम ने यह भी रेखांकित किया कि इस परीक्षण के माध्यम से दुनिया उनके सामरिक परमाणु हथियार की विनाशकारी शक्ति को बेहतर ढंग से समझ सकेगी। दक्षिण कोरियाई सेना के अनुसार, शनिवार को उत्तर कोरिया की ओर से पूर्वी सागर में लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है। परिषद ने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों का सीधा उल्लंघन बताया है जो उत्तर कोरिया की किसी भी प्रकार की बैलिस्टिक गतिविधियों पर रोक लगाते हैं। जानकारों का मानना है कि 420 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले इन रॉकेट्स का मुख्य निशाना दक्षिण कोरिया और वहां तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। इस सैन्य निरीक्षण के दौरान किम जोंग उन की बेटी, किम जू ऐ भी उनके साथ नजर आईं। लगभग 13 वर्षीय किम जू ऐ 2022 के अंत से ही प्रमुख सैन्य परेडों और हथियार परीक्षणों में अपने पिता के साथ सक्रिय रूप से दिखाई दे रही हैं। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे हैं।

चलती हाईवे पर इफ्तार कर विवादों में घिरीं मशहूर व्लॉगर सबा इब्राहिम

नई दिल्ली, एजेंसी। टीवी अभिनेता शोएब इब्राहिम की बहन और मशहूर व्लॉगर सबा इब्राहिम एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक खतरनाक लापरवाही है। अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली व्लॉग्स के लिए जानी जाने वाली सबा हाल ही में मुंबई से अपने पति खालिद नियाज के गांव मौदहा जा रही थीं। इसी सफर के दौरान उन्होंने अपनी गाड़ी बीच रास्ते में एक व्यस्त हाईवे के किनारे रोक दी। हैरान करने वाली बात यह थी कि सबा, उनके पति और परिवार के अन्य सदस्य चलते हाईवे की सड़क पर ही चादर बिछाकर बैठ गए और इफ्तार करने लगे। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि जिस जगह वे बैठे थे, वहां से तेज रफ्तार गाड़ियां बेहद करीब से गुजर रही थीं। जैसे ही यह व्लॉग सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने सबा और उनके पति खालिद की जमकर क्लास लगानी शुरू कर दी। नेटिजन्स का कहना है कि यह न केवल खतरनाक है, बल्कि यातायात नियमों का भी खुला उल्लंघन है। लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि उनके साथ परिवार में छोटे बच्चे भी मौजूद थे, ऐसे में हाईवे जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह बैठना किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई लोगों ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि अगर सड़क पर कोई अनियंत्रित वाहन उनके करीब आ जाता, तो इस जानलेवा लापरवाही का जिम्मेदार कौन होता? कुछ यूजर्स ने तो उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग तक कर दी है। लोगों का मानना है कि एक प्रभावशाली व्लॉगर होने के नाते सबा की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने लाखों फॉलोअर्स को सुरक्षा और नियमों के प्रति जागरूक करें, न कि इस तरह के जोखिम भरे कृत्यों को बढ़ावा दें। फिलहाल, सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर सबा इब्राहिम और उनका परिवार कड़े विरोध का सामना कर रहा है।

सरकार के सख्त दिशा-निर्देश जारी- डिब्बों या खुले बर्तनों में पेट्रोल-डीजल जमा करना पड़ेगा भारी!

नई दिल्ली , एजेंसी। देश में ईंधन की आपूर्ति को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर चल रही विभिन्न अटकलों के बीच प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर नागरिकों से पैनिक न करने की अपील की है। मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि देश भर के पेट्रोल पंपों और खुदरा विक्रेताओं के पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए घबराने या अनावश्यक भंडारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि डिब्बे या खुले वर्तनों में डीजल पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपूर्ति की स्थिरता के साथ-साथ, सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पेट्रोलियम विभाग ने ईंधन की खरीद और भंडारण के संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अधिकारियों ने नागरिकों को सख्त हिदायत दी है कि वे खुले बर्तनों, कांच की बोतलों या अनुपयुक्त प्लास्टिक के डिब्बों में ईंधन कतई न लें। प्रशासन के अनुसार, असुरक्षित तरीके से ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण करना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि यह भीषण अग्नि दुर्घटनाओं और जन-धन की हानि का कारण बन सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता केवल अपनी जरूरत के अनुसार वाहनों के टैंक में ही ईंधन भरवाएं और घरों में इसका संचय न करें। नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। देशभर के डीलरों से कहा गया है कि वे ईंधन वितरण के दौरान सुरक्षा मानकों से कोई समझौता न करें। यदि कोई पंप संचालक मानकों का उल्लंघन कर असुरक्षित कंटेनरों में पेट्रोल या डीजल भरते हुए पाया जाता है, तो प्रशासन द्वारा उसका लाइसेंस रद्द करने जैसी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को इन नियमों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अंत में स्पष्ट किया कि रिफाइनरियों से लेकर रिटेल आउटलेट्स तक की पूरी सप्लाई चेन सुचारू रूप से कार्य कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईंधन की उपलब्धता बनी रहे और सुरक्षा संबंधी किसी भी जोखिम को शून्य किया जा सके।

मुश्किल में बादशाह: आयोग की सख्ती के बीच बिश्नोई गैंग ने दी जान से मारने की धमकी

पानीपत, एजेंसी। मनोरंजन जगत के चर्चित रैपर बादशाह इन दिनों दोहरे संकट में घिर गए हैं। एक ओर जहां उनके नवीनतम हरियाणवी गीत टटीरी को लेकर कानूनी और सामाजिक विरोध तेज हो गया है, वहीं दूसरी ओर कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी देकर सनसनी फैला दी है। पानीपत में हुई एक हालिया फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी लेते हुए गैंग ने बादशाह के नाम एक चेतावनी भरा संदेश जारी किया है, जिससे पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। शनिवार को पानीपत के असंध रोड स्थित वेस्टर्न यूनियन के कार्यालय पर अज्ञात हमलावरों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस वारदात की जिम्मेदारी रंदीप मलिक और अनिल पंडित (यूएसए) ने ली है, जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी माना जाता है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक पोस्ट में गैंग ने दावा किया कि यह फायरिंग हवाला कारोबारियों के लिए महज एक ट्रेलर थी। हालांकि, इस पोस्ट के अंत में सीधे तौर पर बादशाह को निशाना बनाते हुए लिखा गया कि उन्होंने हरियाणा की संस्कृति को खराब करने का प्रयास किया है। संदेश में चेतावनी दी गई है कि साल 2024 में उनके क्लब में जो हुआ वह सिर्फ एक झलक थी, लेकिन अगली बार अंजाम बहुत बुरा होगा। गैंग का आरोप है कि बादशाह अपने गानों के जरिए हरियाणा की छवि और सांस्कृतिक मूल्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। विवादों का सिलसिला केवल धमकी तक ही सीमित नहीं है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को निर्देश दिए हैं कि यदि बादशाह जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, तो उनका पासपोर्ट जब्त कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आयोग का मानना है कि कलाकारों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मर्यादा लांघने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।विरोध की यह आंच अब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में बादशाह के सभी कार्यक्रमों और आयोजनों पर रोक लगाने की मांग की है। उनका तर्क है कि गानों में अश्लीलता का प्रदर्शन और स्कूल ड्रेस का अनुचित उपयोग समाज, विशेषकर युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने की घातक एयरस्ट्राइक

काबुल, एजेंसी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी सीमा विवाद अब एक खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हालिया सुरक्षा रिपोर्टों और सूत्रों के हवाले से एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है कि पाकिस्तान वायुसेना ने कंधार के कैंप गेको में एक बेहद सटीक और बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले का मुख्य उद्देश्य अफगान तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा को निशाना बनाना था। यदि यह दावा पूरी तरह पुष्ट होता है, तो इसे केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को हिला देने वाली घटना माना जाएगा। यह भीषण हमला शुक्रवार तड़के उस समय किया गया, जब खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह संकेत मिले थे कि हैबतुल्लाह अखुंदजादा पिछले कुछ हफ्तों से कैंप गेको के एक अत्यंत सुरक्षित परिसर में ठहरे हुए हैं। जमीनी स्तर से आ रही शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, इस एयरस्ट्राइक में कम से कम 22 लोगों के मारे जाने और 50 से अधिक के घायल होने की सूचना है। कंधार, जिसे तालिबान नेतृत्व का आध्यात्मिक और संचालन केंद्र माना जाता है, पिछले 48 घंटों से भारी तनाव और सुरक्षा घेरे में है। इस हमले की तुलना उन चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय अभियानों से की जा रही है, जिनमें किसी देश ने सीधे तौर पर दूसरे देश के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश की हो। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल अभी भी अखुंदजादा की स्थिति को लेकर बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, हवाई हमले ने कैंप गेको की बाहरी सुरक्षा परतों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, लेकिन तालिबान के सुप्रीम लीडर की वर्तमान स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हैबतुल्लाह अखुंदजादा एक अत्यंत गुप्त और बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में रहते हैं। रिपोर्टों में यह भी उल्लेख है कि उनके लिए विशेष रूप से जमीन के नीचे ऐसे बंकरों का निर्माण किया गया है, जो भारी हवाई हमलों को सहने में सक्षम हैं। यही कारण है कि ऊपरी इमारतों के तबाह होने के बावजूद उनके बचने की संभावना बनी हुई है।

जीएसटी ने तेल उपकरण बनाने वाली फर्म पर मारा छापा, पकड़ी 3.4 करोड़ की चोरी

देहरादून, एजेंसी। उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में राज्य कर (स्टेट जीएसटी) विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेल उत्खनन (आयल रिग) के उपकरण बनाने वाली एक प्रमुख फर्म और उसकी सहयोगी इकाइयों पर छापा मारा है। विभाग की इस औचक जांच में करोड़ों रुपये की कर चोरी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद संबंधित फर्मों ने मौके पर ही 3.4 करोड़ रुपये का टैक्स जमा कराया है। आयुक्त राज्य कर सोनिका के निर्देशन में गठित सात टीमों ने एक साथ फर्म के परिसरों पर दबिश दी। जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त फर्म लंबे समय से सुनियोजित तरीके से कर देयता कम करने के खेल में लिप्त थी। विभाग के अनुसार, फर्म फर्जी खरीद और बिक्री के बिलों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का अवैध लाभ उठा रही थी। हैरानी की बात यह है कि फर्म ने अपनी ही सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर कागजों पर फर्जी लेन-देन दिखाया, ताकि विभाग को यह दर्शाया जा सके कि उसने खरीद पर टैक्स अदा किया है और उसे आईटीसी के रूप में वापस प्राप्त किया जा सके। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ ऐसी फर्मों के साथ माल का परिवहन दिखाया गया जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी बिना माल भेजे केवल बोगस बिलों के जरिए कर चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। संयुक्त आयुक्त अजय सिंह और उपायुक्त सुरेश कुमार के मार्गदर्शन में अधिकारियों ने बड़ी संख्या में व्यापारिक दस्तावेज, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डाटा को अपने कब्जे में लिया है। विभाग के पास पुख्ता सबूत होने के कारण, फर्म ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार करते हुए 3.4 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि यह केवल शुरुआती आंकड़ा है। जप्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के गहन परीक्षण के बाद कर चोरी की यह राशि काफी अधिक बढ़ सकती है। इस कार्रवाई में शामिल टीम अब फर्म के पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि नेटवर्क में शामिल अन्य फर्जी इकाइयों का भी पर्दाफाश किया जा सके। इस कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्र के अन्य कर चोरों में हड़कंप मचा हुआ है।

मां रेवा पब्लिकेशन एंड प्रिंटर्स
जबलपुर शहर में सबसे कम दामों में
समाचार पत्र के A to Z कार्य का एकमात्र स्थान
प्रिंटिंग
जॉब वर्क
न्यूज पेपर
पीडीएफ
संपर्क करें
7415685293
9589490996
9340553112
68/1 लक्ष्मीपुर विवेकानंद वार्ड, मुस्कान प्लाजा के पीछे, एम आर 4 रोड, उखरी, जबलपुर (मप्र)

ठेकेदारी प्रथा के साये में पंचायत का निर्माण कार्य, गुणवत्ता पर सवाल – सरकारी धन से बन रही नाली में भ्रष्टाचार की बू

पंचायतों में तेजी से पनप रही ठेकेदारी प्रथा सरकारी नाली निर्माण में भ्रष्टाचार की बू

दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के बंदरबांट के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। जहाँ पंचायत स्तर पर चल रहे निर्माण कार्यों में सरपंच सचिव रोजगार सहायक, और उपयंत्री के द्वारा स्वयं निर्माण एजेंसी होने के वावजूद ठेकेदारों से कार्य करवा जा रहा है जा ठेकेदार के द्वारा ज्यादा बचत के चलते न गुणवत्ता, न ही तकनीकी मानकों और पारदर्शिता को दरकिनार कर मनमानी किए जाने की शिकायतें आम होती जा रही हैं।

आरोप है कि कई जगहों पर सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और उपयंत्री की कथित मिलीभगत से निर्माण कार्यों को ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है, जबकि नियमों के अनुसार पंचायतों में ठेकेदारी प्रथा लागू नहीं होनी चाहिए। कहि सरपंच पति या सचिव या रोजगार सहायक ही ठेकेदार बन बैठे है तो कही अपने परिवार के ही नाम से एजेंसी या फर्म के नाम पर मैटेरियल सप्लायर बन बैठे है बिल लगाकर सरकारी धन धडाधड निकाला जा रहा है और गुणवत्ता से कोई लेनदेना नही और जहाँ कार्य की गुणवत्ता रहे जिसको लेकर सरकार ने एक उपयंत्री नियुक्त किये गए हैं, पर वह अपने घर मे बेठे बेठे ही गुणवत्ता और मूल्यांकन कर रहे है सरपंच सचिव खुद ही साहब के घर फाईल ले जाकर हस्ताक्षर करवा लिए जा रहे है उपयंत्री महोदय को फुर्सत भी नही रहती की मौके में जाकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता माप ले ले उन्हें फाइल में हस्ताक्षर करने का खर्चा पानी भी मिल रहा है। वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत मंडला की ग्राम पंचायत बरगवां के परधान मोहल्ला से सामने आया है, जहां 15वें वित्त आयोग की राशि से लगभग 1 लाख 38 हजार रुपये की लागत से करीब 90 मीटर लंबी नाली का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन यह निर्माण कार्य शुरू से ही सवालों के घेरे में है।

ठेकेदार के भरोसे पंचायत का काम

सूत्रों के अनुसार इस नाली निर्माण का कार्य पंचायत द्वारा सीधे कराने के बजाय अंजनियाझडुंगरिया क्षेत्र के एक ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है। जबकि पंचायतों में निर्माण कार्य मजदूरों के माध्यम से कराया जाना चाहिए। इसके बावजूद खुलेआम ठेकेदारी के जरिये काम कराए जाने से पंचायत व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

नाली निर्माण में सरिया गायब, अभी से दिख रही दरारें

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य पूरी तरह से तकनीकी मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। नाली निर्माण में मजबूती के लिए लोहे की सरिया का उपयोग जरूरी माना जाता है, लेकिन यहां सरिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा। स्थिति यह है कि नाली का निर्माण पूरा होने से पहले ही पीसीसी में जगह-जगह दरारें दिखाई देने लगी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो बरसात के मौसम में यह नाली कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है।

पीसीसी में हनीकॉम्ब, वाइब्रेटर का नहीं हो रहा उपयोग

निर्माण स्थल पर निरीक्षण के दौरान पीसीसी में कई जगह हनीकॉम्ब जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, जो सीधे तौर पर घटिया निर्माण की ओर इशारा करती है। विशेषज्ञों के अनुसार जब कंक्रीट को सही तरीके से जमाया नहीं जाता और पर्याप्त कम्पेक्शन नहीं किया जाता, तब इस प्रकार की स्थिति बनती है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के दौरान वाइब्रेटर का उपयोग भी नहीं किया जा रहा, जबकि पीसीसी निर्माण में वाइब्रेटर का इस्तेमाल बेहद जरूरी होता है। इसके अभाव में कंक्रीट में हवा के बुलबुले रह जाते हैं और निर्माण कमजोर हो जाता है।

सूचना बोर्ड भी नहीं, पारदर्शिता पर सवाल

सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होता है, जिसमें योजना का नाम, लागत, निर्माण अवधि और जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी दी जाती है। लेकिन इस निर्माण स्थल पर ऐसा कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया, जिससे कार्य की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

मजदूरों ने भी खोली पोल

मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि उन्हें बिना सरिया के ही नाली निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं। मजदूरों के अनुसार मसाला तैयार करते समय 12 तसला गिट्टी, 13 तसला रेत और एक बोरी सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह अनुपात तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं है तो निर्माण की मजबूती प्रभावित होना तय है।

शिकायतें होती हैं, कार्रवाई नहीं

ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के जिम्मेदार लोग गुणवत्ता की जांच करने के बजाय केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब भी इस तरह के मामलों की शिकायत की जाती है तो कागजी जांच का भरोसा दिया जाता है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई शायद ही कभी होती है।

सरकारी धन की बबार्दी का खतरा

नाम न छापने की शर्त पर कई ग्रामीणों ने बताया कि सरकार गांवों के विकास के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन यदि निर्माण कार्य ही घटिया होंगे तो ग्रामीणों को इसका लाभ कैसे मिलेगा। उनका कहना है कि यदि नाली जैसी बुनियादी सुविधा कुछ ही महीनों में टूट जाती है तो यह सीधे-सीधे सरकारी धन की बबार्दी है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराए जाने और पंचायत कार्यों में ठेकेदारी प्रथा के इस्तेमाल की भी जांच करने की मांग की है। साथ ही यदि निर्माण में अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है।

अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर

अब सवाल यह है कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। यदि समय रहते जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो यह मामला भी पंचायत स्तर पर चल रहे भ्रष्टाचार की एक और मिसाल बनकर रह जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों की नजर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्रवाई पर टिकी हुई है। लोगों का कहना है कि यदि इस मामले में सख्त कदम उठाए गए तो न केवल इस निर्माण कार्य की सच्चाई सामने आएगी, बल्कि अन्य पंचायतों में चल रहे ऐसे कार्यों पर भी लगाम लग सकेगी। जिससे सरकारी धन को बबार्दी होने से बचाया जा सकें।

परीक्षा पास, अनुभव भी पूरा, फिर भी नियुक्ति नहीं!

दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग-1, 2 और 3 उत्तीर्ण कर चुके सैकड़ों अतिथि शिक्षक आज भी सरकारी स्कूलों में नियमित नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। वर्षों तक स्कूलों में पढ़ाने का अनुभव रखने के बावजूद उन्हें स्थायी पद नहीं मिल पा रहा है, जिससे शिक्षकों में भारी नाराजगी और निराशा देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा चिंता की स्थिति महिला अतिथि शिक्षकों की है, जिन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कठिन तैयारी कर परीक्षा पास की, लेकिन नियुक्ति अब भी दूर की कौड़ी बनी हुई है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने शासन द्वारा आयोजित चयन परीक्षा पास कर ली है और उनके पास वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र भी है। इसके बावजूद सरकार की ओर से उन्हें नियमित शिक्षक के रूप में पदस्थापित नहीं किया जा रहा। कई शिक्षक वर्तमान में स्कूलों में कार्यरत नहीं हैं, जबकि कुछ अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन स्थायी रोजगार न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। एक महिला अतिथि शिक्षिका ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ह्लहमने परीक्षा पास कर ली, अनुभव भी है, फिर भी हमें नियमित नियुक्ति नहीं दी जा रही। अगर नियमित शिक्षक बन जाएं तो स्थिर वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा।ह्व अतिथि शिक्षकों का यह भी कहना है कि प्रदेश स्तर पर नियमित भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही जा रही है, लेकिन जो उम्मीदवार पहले ही चयन परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें सीधे सरकारी स्कूलों में नियमित पद पर क्यों नहीं रखा जा रहा।

स्कूलों में शिक्षकों की कमी, फिर भी नियुक्ति नहीं-मंडला जिले के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विडंबना यह है कि वर्षों से इन्हीं स्कूलों को संभालने वाले अतिथि शिक्षक ही आज नियमित नियुक्ति के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

विधायकों पर भी उठे सवाल

अतिथि शिक्षकों ने जिले के जनप्रतिनिधियों और विधायकों से भी सवाल किया है कि आखिर यह मुद्दा विधानसभा में क्यों नहीं उठाया जा रहा। उनका कहना है कि यदि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने और आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि चयन परीक्षा पास कर चुके सभी योग्य अतिथि शिक्षकों, विशेषकर महिलाओं को तत्काल नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके और वर्षों से संघर्ष कर रहे शिक्षकों को न्याय मिल सके।

खाईबाज मालामाल, जनता हलकान – गली-चौराहों पर खुलेआम चल रहा सट्टा-पट्टी का खेल, महीना हप्ता के चलते चल रहा है खुला खेल

दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। जिले के विकास खंड नैनपुर नगर इन दिनों अवैध सट्टा-पट्टी के जाल में बुरी तरह जकड़ता नजर आ रहा है। नगर के कई गली-चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर खुलेआम सट्टे के अंक लिखे जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ दिन-दहाड़े हो रहा है, और पुलिस थाना परिसर के आसपास से लेकर ग्रामीण कस्बों तक मकड़ जाल खाईबाज ने फैला रखा है और यह सब नैनपुर पुलिस की नाक के नीच चल रहा है और आज सट्टा के खाईबाज पुलिस विभाग के नैनपुर से लेकर जिले तक मे बैठे आला अधिकारियों को अपनी जेब मे रखने की बात खुलेआम गली चौराहों में कहते नजर आ रहे है। और इनके बड़बोलेपन से जनता को कह रहे है कि जेब मे पैसा हो तो सब बिकते है बस बोली लगाने वालों में दम होना चाहिये नाम न छापने की तर्ज में बताया गया कि आज ये खाईबाज कहते है कि पुलिस और पुलिस कप्तान कुछ नही कर सकता है क्योंकि हम इन्हें हप्ता और महीना पहुँचा रहे है और अगर ज्यादा शिकवा शिकायत होती है तो हम अपने छोटे मोटे लिखने वालों को कुछ पट्टी और पेसो के साथ पुलिस से केस बनवा लेते है फिर जनता भी शांत और पुलिस भी अपनी वाहवाही लूट लेती है और फिर दूसरे दिन से वही खेल चालू कोई बड़ी

नैनपुर में सट्टा साम्राज्य का खुलासा

कायार्वाही नही होती है कोर्ट में भी छोटा मोटा जुमार्ना देकर हम अपने लड़को बाहर कर फिर से काम मे लगा देते हैं। लेकिन जिम्मेदार विभागों की कार्रवाई अब तक कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसे में लोगों के बीच चर्चा है कि ह्लपुलिस मालामाल है और जनता हलकानह्व। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर में कुछ नए-नए खाईबाज तेजी से उभरे हैं, जो सट्टा-पट्टी के इस अवैध धंधे से देखते ही देखते लाखों-करोड़ों के खेल में उतर चुके हैं। बाहर से खुद को गरीब और बेरोजगार बताने वाले ये लोग अंदरखाने रोज हजारों-लाखों रुपये की सट्टा-पट्टी हजम कर रहे हैं।

गरीब बनने का नाटक, अंदर लाखों का खेल- सूत्रों के अनुसार नगर में सक्रिय कई खाईबाज खुद को मजदूरी करने वाला बताते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे रोजाना बड़ी रकम की सट्टा-पट्टी अंदर कर रहे हैं। दिखावे के लिए जेब में सौ-दो सौ रुपये लेकर घूमना और खुद को गरीब बताना इनकी पुरानी चाल बताई जाती है, जबकि इस अवैध कारोबार से इन्होंने मोटी संपत्ति खड़ी कर ली है। नगर के लोगों का कहना है कि इन सट्टेबाजों के कारण कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। कुछ लोगों को कर्ज में डूबना पड़ा, तो कई लोगों के घर-मकान तक बिक गए। इसके बावजूद इन खाईबाजों पर कोई ठोस कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है।

गली-गली बैठ रहे खाईबाज

स्थानीय नागरिकों के मुताबिक नैनपुर नगर के कई चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर रोजाना तय समय पर सट्टा-पट्टी लिखने वाले लोग बैठ जाते हैं। वहां खुलेआम अंक लिखे जाते हैं और पैसे का लेन-देन भी किया जाता है। लोगों का कहना है कि यह सब कुछ इतने खुले तरीके से हो रहा है कि मानो सट्टेबाजों को कानून का कोई डर ही नहीं रह गया है। कई स्थानों पर तो शासकीय संस्थानों और स्कूलों के आसपास भी यह अवैध गतिविधि देखी जा रही है, जिससे सामाजिक माहौल पर भी बुरा असर पड़ रहा है।

युवाओं को बना रहा जुए का आदी- नगर के सामाजिक कार्यकताओं का कहना है कि सट्टा-पट्टी का यह बढ़ता जाल युवाओं के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जल्दी पैसा कमाने के लालच में कई युवा इस जुए के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं और धीरे-धीरे उनकी पढ़ाई, रोजगार और पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

प्रशासन पर उठते सवाल

नगर में खुलेआम चल रहे इस अवैध सट्टा कारोबार ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिकों का कहना है कि जब गली-गली सट्टा-पट्टी लिखी जा रही है तो यह जिम्मेदार अधिकारियों की नजर से कैसे बच सकती है। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस और प्रशासन सच में कार्रवाई करना चाहें तो इस अवैध धंधे पर तुरंत लगाम लग सकती है। लेकिन लगातार बढ़ते इस नेटवर्क को देखकर नगर में यह चर्चा भी आम हो चली है कि आखिर इस कारोबार को संरक्षण कौन दे रहा है।

कार्रवाई की मांग तेज

नगर के जागरूक नागरिकों और समाजसेवियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि नैनपुर में चल रहे इस अवैध सट्टा नेटवर्क के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

इनका कहना है

ह्लनैनपुर नगर के कई चौराहों पर खुलेआम सट्टा-पट्टी लिखी जा रही है। खाई बाजो ने अपना पैसा के रुतबे के चलते न इन्हें पुलिस का भय बल्कि बेखौफ यह खेल चल रहा हैं यह अवैध गतिविधि युवाओं को बर्बाद कर रही है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

समाजसेवी, नैनपुर

खबर कवरेज करने पहुंचे पत्रकार को खदान में बनाया बंधक, मैनेजर सहित कर्मचारियों पर एफआईआर

मोबाइल छीना, वीडियो डिलीट किए, तोड़ने का किया प्रयास – पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ मामला

दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। जिले में संचालित डोलोमाइट खदानों में मनमानी और अवैध गतिविधियों के आरोप पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार खबर कवरेज के लिए खदान क्षेत्र में पहुंचे एक पत्रकार को खदान के कर्मचारियों ने घेरकर बंधक बनाने की कोशिश की, मोबाइल छीन लिया और उसमें मौजूद वीडियो व फोटो जबरन डिलीट कर दिए। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन तोड़ने का भी प्रयास किया गया और प्रेस आईडी तक तोड़ दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने ककैया डोलोमाइट माइन के मैनेजर योगेशराज पटेल सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के सामने आने के बाद जिले के पत्रकारों में आक्रोश देखा जा रहा है। खबर कवरेज करने पहुंचे थे पत्रकार के अनुसार मंडला निवासी रामकुमार उर्फ रोहित बघेल, जो विस्तार न्यूज चैनल में जिला रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं, 18 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत बीजेगांव क्षेत्र में खबर कवरेज के लिए पहुंचे थे। गांव के आसपास संचालित डोलोमाइट खदानों में हो रही ब्लास्टिंग और खनन को लेकर ग्रामीणों में लंबे समय से असंतोष और भय का माहौल बना हुआ है। कि खदानों में लगातार विस्फोट किए जा रहे हैं, जिससे आसपास के घरों में कंपन महसूस होता है और कई मकानों में दरारें भी पड़ चुकी हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने पहले भी प्रशासन और खनिज विभाग को शिकायतें की थीं। इसी सूचना के आधार पर पत्रकार रोहित बघेल खदान क्षेत्र में वास्तविक स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। **वीडियो बनाते ही भड़क उठे कर्मचारी-** बताया जाता है कि जब पत्रकार खदान परिसर में पहुंचे तो वहां ट्रकों में डोलोमाइट पत्थर लोड किया जा रहा था। उन्होंने वहां हो रही गतिविधियों के फोटो और वीडियो बनाना शुरू कर दिया।जैसे ही खदान के कर्मचारियों को इसका पता चला, वे आक्रोशित हो गए। आरोप है कि खदान के मैनेजर योगेशराज पटेल और अन्य कर्मचारियों ने पत्रकार को चारों तरफ से घेर लिया और उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी।

मोबाइल छीनकर डिलीट किए वीडियो

पीड़ित पत्रकार के अनुसार कर्मचारियों ने पहले उनका मोबाइल और कैमरा छीन लिया। इसके बाद मोबाइल में मौजूद वीडियो और फोटो जबरन डिलीट कर दिए गए। इतना ही नहीं, एक कर्मचारी ने मोबाइल फोन को तोड़ने की भी कोशिश की। इस दौरान पत्रकार के साथ धक्का-मुक्की भी की गई और उन्हें खदान परिसर में ही रोककर रखा गया। पत्रकार का आरोप है कि कर्मचारियों ने उन्हें वहां से बाहर निकलने नहीं दिया और डराने-धमकाने की भी कोशिश की। **प्रेस आईडी तक तोड़ दी-** घटना के दौरान कर्मचारियों ने पत्रकार की पहचान के लिए रखी गई प्रेस आईडी को भी तोड़ दिया। इस पूरी घटना के दौरान पत्रकार खुद को असुरक्षित स्थिति में महसूस कर रहे थे। काफी देर तक चले इस घटनाक्रम के बाद पत्रकार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल हस्तक्षेप किया। **पुलिस के हस्तक्षेप से निकले बाहर-** बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद बम्हनी थाना प्रभारी और मंडला थाना प्रभारी सक्रिय हुए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही पत्रकार खदान परिसर से बाहर निकल पाए। इस घटना के बाद पत्रकारों में भारी नाराजगी फैल गई और पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचा। उन्होंने घटना से जुड़े प्रमाण भी पुलिस को सौंपे। **जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर-** घटना के बाद पत्रकार रामकुमार बघेल ने बम्हनी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और पीड़ित पत्रकार के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने खदान के मैनेजर योगेशराज पटेल सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 130, 127(2), 324(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई तथ्यों के आधार पर की जाएगी। **खदानों में अनियमितताओं की चर्चा-** सूत्रों के अनुसार बम्हनी बंजर क्षेत्र में संचालित कई डोलोमाइट खदानों में लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायतें मिलती रही हैं। आरोप है कि कई खदानों में स्वीकृत क्षमता से अधिक खनन किया जा रहा है और इसकी नियमित जांच भी नहीं हो रही है। इसके अलावा खदानों से बड़ी मात्रा में पत्थर निकालकर ओवरलोड ट्रकों में भरकर बाहर भेजा जा रहा है।

युवती के अपहरण के तीन आरोपियों को स्कॉर्पियो वाहन सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। जिले के थाना जैतहरी में पीड़िता द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि जयप्रकाश राठौर द्वारा उसे जबरन स्कॉर्पियो वाहन में बैठाकर विवाह के उद्देश्य से अपहरण किया। युवती की रिपोर्ट पर थाना जैतहरी में अपराध कायम कर विवेचना में लिया। पीड़िता ने बताया कि वह पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल में अध्ययनरत है। लगभग तीन वर्ष पूर्व उसकी इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से जयप्रकाश राठौर (निवासी चोरभठी) से पहचान हुई थी। फोन पर हुई बातचीत में जयप्रकाश ने उससे विवाह करने की बात कही, लेकिन पीड़िता ने स्पष्ट किया कि वह केवल अपने माता-पिता की इच्छा अनुसार ही विवाह करेगी और दिनांक 28 फरवरी 2026 से वह अपने बड़े पापा के घर जैतहरी में आकर रह रही थी। दिनांक 13 मार्च 2026 को दोपहर में जब वह अपनी सहेली के साथ घर के बाहर बैठी थी। तभी एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से जयप्रकाश राठौर, जिसने अपना चेहरा साफे से ढका था ने पीड़िता को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया। वाहन में चालक सहित एक अन्य व्यक्ति पिपरिया पहुंचकर पीड़िता को सुरक्षित वापस ले आए। पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए। जैतहरी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज कुछ घंटे में अपहरण में शामिल तीनो आरोपी जयप्रकाश राठौर, पिता ललन राठौर, उम्र 23 वर्ष, निवासी चोरभठी थाना जैतहरी, शुभम राठौर, पिता दुलारे राठौर, उम्र 23 वर्ष, निवासी बेला, थाना अनूपपुर, सागर पटेल, पिता संतोष पटेल, उम्र 22 वर्ष, निवासी मौहरी, थाना कोतवाली अनूपपुर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना भी मौजूद था। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्परता से वाहन और आरोपियों का पीछा किया। जयप्रकाश ने पिपरिया में पीड़िता को छोड़कर भाग गया। वहां ग्रामीण और पीड़िता के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। उसके भाई और मामा में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक टढ 65 इ 4472 को जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय अनूपपुर में पेश किया गया जहां से रिमांड पर जिला जेल अनूपपुर भेजा गया है।

सामाजिक सद्भावना बढाता है रंगों का पावन पर्व होली, जिला विकास मंच ने स्थापित की उत्कृष्ट परंपरा

मिड – वे ट्रीट किरर मे होली मिलन समारोह सम्पन्न

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनुपपुर। भारतीय सनातन परंपरा मे रंगों का पावन पर्व होली सामाजिक सद्भावना बढाने मे सहायक रहा है। होली का पर्व हमें एक साथ मिलजुल कर रहने और परंपराओं के निर्वहन की शिक्षा देता है।? अनूपपुर जिला विकास मंच द्वारा मिड वे ट्रीट किरर ,पुष्पराजगढ़ में आयोजित होली मिलन समारोह विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरिमापूर्ण ,उत्साह के साथ मनाया गया । इस अवसर पर होली की शुभकामनाएँ देते हुए कार्यक्रम मे मध्यप्रदेश शासन के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने उपरोक्त विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि आज के दौर मे तनावपूर्ण जीवन मे होली मिलन समारोह के माध्यम से हम सभी लोग आपस मे एक साथ मिलजुल कर रंगोत्सव मनाते हैं ,तो बचपन की होली ध्यान आती है। जब हम? सभी लोग बिना भेदभाव के खुशियों भरा यह त्यौहार मनाते थे। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने क्षेत्र वासियों को होली पर्व की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि भारतीय परंपराओं मे त्योहारों के आयोजन की परंपरा जीवन मे उत्साह का संचार करती है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमे कोई जाति,वर्ण, भाषा,प्रांत, गरीबी - अमीरी का भेद नहीं होता। अनूपपु कलेक्टर हर्षल पंचोली ने आयोजन की मुक्त कंठ सराहना करते हुए कहा कि अनूपपु जिला विकास मंच ने पिछले वर्ष भी होली मिलन का गरिमामयी समारोह आयोजित किया था। इस वर्ष भी वनांचल के शांत मनोरम स्थल पर होली मिलन का आयोजन कर इसे परंपरा का स्वरूप दे दिया है। उन्होंने जिले के लोगों को नशामुक्त, स्नेहिल और सौहार्दपूर्ण होली मनाने के लिये धन्यवाद दिया। जिला विकास मंच के संयोजक मनोज द्विवेदी ने होली पर्व की शुभकामनाएँ देते हुए कार्यक्रम मे शामिल जिले भर से आए अतिथियों के प्रति आभार जताया। होली मिलन समारोह मे शामिल अतिथियों और गणमान्य लोगों ने हर्षोल्लास के साथ रंगोत्सव मनाया। लोगो ने समभाव से खुशियाँ मनाते हुए एक दूसरे को अबीर - गुलाल लगाकर शुभकामनाएँ दीं। शुरूआत मे लोग मंत्री दिलीय जायसवाल और कलेक्टर हर्षल पंचोली को रंग लगाने मे झिझकते दिखे। लेकिन उनके सहज, सरल ,प्रेमपूर्ण व्यवहार से कुछ ही देर मे लोगों ने जमकर रंग, गुलाल उडाया।

कपड़ा दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, पुलिस जांच में जुटी

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक तीर्थ स्थल पवित्र नगरी अमरकंटक में एक कपड़ा दुकान में अचानक आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। यह घटना नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 12 स्थित मुख्य मार्ग पर संचालित विहान गारमेंट्स एवं रेडीमेड कपड़ा दुकान में हुई। बंद दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लगभग डेढ़ लाख रुपये मूल्य का कपड़ा, काउंटर तथा आलमारी जलकर नष्ट हो गए। आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, हालांकि प्रारंभिक तौर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है। सूचना मिलते ही पास में रहने वाले नागेश्वर यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान के शटर का ताला तोड़कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। साथ ही नगर परिषद अमरकंटक को भी फायर ब्रिगेड के लिए सूचना दी गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से पानी डालकर आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे आग और अधिक फैलने से बच गई। उक्त दुकान नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद देवानंद खत्री की पत्नी श्रीमती हर्षिता खत्री द्वारा संचालित की जाती है। घटना की सूचना मिलते ही खत्री दंपति मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने में सहयोग किया। घटना की प्राथमिक सूचना अमरकंटक थाना पुलिस को दे दी गई है तथा राजस्व विभाग को भी अवगत करा दिया गया है। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा आग लगने के कारणों की जांच-पड़ताल की जा रही है। इस घटना में खत्री दंपति को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।

लोक अदालत ने सुलझाया 7 साल पुराना घर मालिकाना हक का विवाद

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनुपपुर। सात वर्षों से चले आ रहे एक लंबे कानूनी विवाद का पटाक्षेप आज लोक अदालत में हो गया। कोतमा तहसील के जमुना क्षेत्र में दो पड़ोसी परिवारों के बीच घर के मालिकाना हक को लेकर शुरू हुआ यह झगड़ा कोर्ट में पहुंचा था, जो हिंसक झड़पों तक पहुंच गया था।विवाद की शुरूआत 2019 में हुई जब पड़ोसी राठौर परिवारों ने एक ही संपत्ति पर दावा ठोका। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर घर पर कब्जा करने का आरोप लगाया, जिससे कई बार लाठी-डंडों से मारपीट और पुलिस हस्तक्षेप की नौबत आई। सात सालों में दर्जनों सुनवाईयों के बावजूद मामला सुलझा नहीं था, जिससे दोनों परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से त्रस्त हो चुके थे। लोक अदालत में न्यायाधीश अमनदीप सिंह छाबड़ा के प्रयासों से दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने के लिए प्रेरित किया गया और विस्तृत चर्चा तथा समझाइश के बाद दोनों पक्षों ने समझौते पर सहमति व्यक्त की।समझौते के बाद दोनों पक्षों ने कहा, 7 साल की लड़ाई ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लोक अदालत ने हमें शांति दी। अब हम पड़ोसी की तरह रहेंगे।

आज होगा खदान बंद किसानों के नायिक लड़ाई में पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा

दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। जिले के रामपुर बटुरा खुली खदान परियोजना प्रभावित किसानों की बैठक में पड़रिया ग्राम पंचायत भवन में आस पास के रामपुर,बटुरा, खैरबना, बैरिहा, पड़रिया, खाड़ा, बटुरा, चाका , अतरिया, बिछिया, कोदेली, के सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। मुख्य मुद्दा सभी अधिग्रहित गांव का मुआवजा भुगतान एक साथ करें, विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्स्थापना, संपूर्ण परिसंपत्ति, का मुआवजा भुगतान एक साथ तत्काल करें, रोजगार में प्राएर्थमिकता दे , सी एस आर और ई आर, दोनों मद का निर्माण में लगाया जाए छूटे हुए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही तत्काल करें, स्वास्थ्य शिक्षा आवास के क्षेत्र का एवं पर्यावरण को भी प्रारतमिकता दे, मुख्य रूप से रामपुर टगरा टोला से सादा तिराहा तक विद्युतीकरण रोड मरम्मत को तत्काल करें। पूर्व में ज्ञापन के द्वारा या बैठक में विषय आपको दी गई उन सभी विषयों को गंभीरता से लेते हुए किस काम में कितना समय लग रहा है, समय सहित चिन्हित कर किसानों के समक्ष प्रस्तुत करें। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व एसडीएम जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व अध्यक्ष रमेश सिंह, जिला पंचायत सदस्य शांति मनमोहन चौधरी, जनपद सदस्य सभापति वन समिति चंद्र कुमार तिवारी, सांसद प्रतिनिधि राजकमल मिश्रा, किसान नेता आदित्य त्रिपाठी, जुझारू नेता आनंद त्रिपाठी, ओम प्रकाश द्विवेदी,अखिलेश त्रिपाठी पत्रकार, नीलकंठ, उप सरपंच जुली बिछिया नीलू राव, अशोक पटेल, कन्हैया पटेल, राजेंद्र पटेल, उप सरपंच, पुरुषोत्तम पटेल, कोडयली, लल्ला साहू, उद्योग साहू श्रीनिवास तिवारी, सहित अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे प्रेस के माध्यम से अनूपपुर एवं शहडोल जिले के समस्त सामाजिक संगठनों किसान संगठनों एसईसीएल से जुड़े यूनियन पदाधिकारी एवं साथी हमारे क्षेत्र के सभी किसान दोनों जिले के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया आप सभी से आंदोलन समिति का अपील की है सुबह 10:00 बजे आंदोलन स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को सहयोग करें एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील निगम का स्वागत करें। यह आंदोलन को समर्थन करने के लिए भोपाल से चलकर देश भर में संघर्ष करने वाले किसानों के नेतृत्व करने वाले ऊजार्वान किसान नेता को सुने और अपनी सुनाए।

नेशनल लोक अदालत का किया गया आयोजन, 2749 प्रकरणों का हुआ निराकरण

न्यायालय ने पति पत्नी के बीच कराया सुलह

दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निदेर्शानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल काशीनाथ सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय शहडोल एवं सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढ़ार तथा जयसिंहनगर में किया गया। जिला शहडोल में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय शहडोल एवं सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढ़ार तथा जयसिंहनगर में कुल 23 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया। इनमें जिला न्यायालय शहडोल में 11 खंडपीठ, श्रम न्यायालय शहडोल के श्रम न्यायाधीश अभिषेक कुमार त्रिपाठी की 1 खंडपीठ, तहसील न्यायालय ब्यौहारी में 4 खंडपीठ, तहसील न्यायालय बुढ़ार में 4 खंडपीठ तथा तहसील न्यायालय जयसिंहनगर में 3 खंडपीठ गठित किए गए। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय परिसर में विद्युत विभाग, नगरपालिका, राष्ट्रीयकृत बैंक एवं बीएसएनएल सहित अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। इस नेशनल लोक अदालत में कुल 552 लंबित प्रकरण एवं 2197 प्री-लिटिगेशन प्रकरण, इस प्रकार कुल 2749 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें कुल 4,14,38,985 रुपये की राशि का अवार्ड पारित हुआ। इनमें मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के 46, चेक अनादरण के 61, आपराधिक राजीनामा योग्य 177, वैवाहिक विवाद के 42, विद्युत विभाग के 47 लंबित एवं अन्य 179 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

पति पत्नी में हुआ सुलह

शुभम सिंह एवं शिवानी का विवाह के तीन वर्ष बाद में छोटी-छोटी बातों को लेकर उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण पति-पत्नी अलग रहने लगे। वादी शुभम सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक पुनर्स्थापन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। कुटुंब न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को विशेष प्रयास कर समझाइश दी गई तथा अधिवक्ताओं के सहयोग से दोनों ने अपने मतभेद भुलाकर पुनः एक साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। इसके पश्चात दोनों ने एक-दूसरे को माला पहनाकर अपने विवाद का अंत किया और साथ-साथ न्यायालय से रवाना हुए। इसी प्रकार रीतेष वर्मन एवं सुजाता का विवाह के बाद 2023 अलग रहने लगे। वादी रीतेष वर्मन द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र में मोबाइल का उपयोग, वीडियो हुआ वायरल, सहायक संचालक दिलीप मराठा पर उठे सवाल

दैनिक रेवांचल टाइम्स उमरिया। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक पर्यटन दिलीप कुमार मराठा के नियम विरुद्ध कार्य शैली के कारण एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। इस बार मामला टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में सफारी के दौरान मोबाइल फोन के कथित उपयोग से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों ने पर्यटन प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 13 मार्च 2026 की शाम की सफारी के दौरान ताला जोन में वीआईपी पर्यटकों के साथ भ्रमण के समय चर्चित ह्यबजरंगह्ल टाइगर दिखाई दिया। इसी दौरान वायरल वीडियो में टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक (ताला) दिलीप कुमार मराठा कथित रूप से मोबाइल फोन से टाइगर की फोटो और वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 17 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार में किसी भी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप रोकने के उद्देश्य से पर्यटन गतिविधियों पर सख्त दिशा-निर्देश लागू करने पर जोर दिया था। ऐसे में संरक्षित क्षेत्र के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर उठे सवालों ने पूरे प्रकरण को चर्चा में ला दिया है। सफारी में मौजूद कुछ पर्यटकों ने भी इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि जब सफारी के दौरान गाइड और वन अमला पर्यटकों को मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर सख्ती से निर्देश देता है, तो अधिकारियों द्वारा स्वयं इसका उपयोग किए जाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सहायक संचालक दिलीप मराठा का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। विभागीय सूत्रों के अनुसार पूर्व में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और गाली-गलौज के आरोपों को लेकर भी वे चर्चा में रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि पूर्व में इसी प्रकार के विवादों के चलते मराठा को निलंबित भी किया गया था, मगर न्यायालय से निलंबन आदेश पर स्थगन प्राप्त कर लिया। इसके बाद से वे लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ बताए जाते हैं, जिस पर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं।

प्रताड़ना से परेशान महिला ने की थी आत्महत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। जिले के बुढ़ार थाना अंतर्गत चौकी केशवाही क्षेत्र में एक महिला को लगातार प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतिका ग्राम पंचायत बलबहरा में मोबिलाइजर के रूप में कार्यरत थी। घटना के बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 11 मार्च 2026 को ग्राम पंचायत भवन बलबहरा में मोबिलाइजर सुनैना कुशवाहा (30) पत्नी सुरेन्द्र कुशवाहा निवासी बलबहरा ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, शव पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों व अन्य साक्षियों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि गांव का ही निवासी मुरारीलाल सोनी उर्फ मुरारी (33) पिता अशोक कुमार सोनी बीते 7-8 महीनों से महिला को लगातार परेशान कर रहा था। आरोपी महिला को अपने साथ रखने की बात कहकर बदनाम करता था और अक्सर गाली-गलौज भी करता था। इतना ही नहीं, वह फोन के माध्यम से भी महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। लगातार हो रही इस प्रताड़ना से महिला काफी मानसिक तनाव में थी। पुलिस के अनुसार इसी प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने 11 मार्च को ग्राम पंचायत भवन बलबहरा में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी मुरारीलाल सोनी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

संपादकीय

बयान और हकीकत के बीच

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने लोकसभा में वक्तव्य देकर देश को आश्वस्त करने की कोशिश की कि कच्चा तेल, पेट्रोल-डीजल, गैस, मिट्टी का तेल और विमानन टरबाइन ईंधन की कोई कमी नहीं है। तेल के पर्याप्त भंडार हैं। हम 40 देशों से कच्चा तेल मंगवा रहे हैं। घरेलू गैस एलपीजी पर दहशत और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैस सिलेंडर की आपूर्ति औसतन अढाई दिन में सुनिश्चित करने के आदेश हैं। सीएनजी की सप्लाई 100 फीसदी है और एलएनजी कार्गो हररोज आ रहे हैं। एलपीजी का उत्पादन 28 फीसदी बढ़ा दिया गया है। मंत्री ने जमाखोरी, कालाबाजारी का भी जिक्र किया। इससे कौन निपटेगा? गैस एजेंसियों के कर्मचारी ही सरेआम घरेलू गैस का सिलेंडर 2500-3000 रुपए में बेच रहे हैं। क्या उन पर अंकुश लगाया जा सकता है? मंत्री ने यह भी कहा कि यह फेक नेरेटिव फैलाने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगभग यही बात कही है, लेकिन वह चुनावी सभाओं में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री या तो देश को संबोधित करें अथवा संसद में आकर बोलें, चुनावी रैलियों की बात पर जनता भरोसा नहीं करती। चूंकि मंत्री ने संसद में बयान दिया है, लिहाजा देश को विश्वास करना चाहिए, लेकिन आंखें जो यथार्थ देख रही हैं, वह क्या है? सडकों पर लोग बिछने लगे हैं। पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ी है और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हैं। रसोई गैस गायब है और अनिश्चित है कि सिलेंडर कब मिलेगा? घर की रसोई में खाना बनेगा अथवा नहीं! तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर को 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर को 114.5 रुपए महंगा क्यों किया? युद्धकाल में ही महंगा क्यों किया गया? इससे भी संवेदनशील सच यह है कि अयोध्या में राम रसोई को बंद करना पड़ा है, जहां औसतन 20,000 से 30,000 लोग रोजाना मुफ्त खाना खाते थे। हालांकि विकल्प तलाशे जा रहे हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में इंडक्शन चूल्हे पर प्रसाद आदि बनाया जा रहा है। बेंगलुरु के बनशंकरी मंदिर में प्रसाद बंद करना पड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय की रसोई बंद कर दी गई है। कुछ पैकबंद और फ्रूट चाट आदि परोसे जा रहे हैं। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ रूट पर गरम, ताजा खाना नहीं मिला, बल्कि पैकबंद खाना परोसा गया। छोटे ढाबे या तो बंदी के कगार पर हैं अथवा उन्होंने एक-दो भोजन बनाने तक ही सीमित कर लिया है। वे डीजल की भी जला रहे हैं। घोर प्रदूषणङ्घ! मुंबई के 50 फीसदी होटल, रेस्तरां भी तालाबंदी की सोच रहे हैं। तमिलनाडु में यह आंकड़ा करीब 10,000 है। अर्थव्यवस्था को झटके लग रहे हैं और रोजगार भी छिन रहा है। इनकी भरपाई कैसे होगी? दरअसल यह भारत का औसतन ऊर्जा-सच है। कई उदाहरण सामने आ रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल गैस भी उपलब्ध नहीं है। भारत 60-66 फीसदी गैस आयात करता है। अब हम 22 लाख टन गैस अमरीका से आयात करेंगे, लेकिन वह गैस 45 दिन के बाद भारत पहुंचेगी। खाड़ी देशों ने युद्ध के कारण आपूर्ति रोक दी है, उत्पादन भी बहुत कम कर दिया है। ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बिल्कुल बंद कर दिया है। पानी के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। ईरानी सैनिक तेल के जहाजों पर हमले कर उन्हें भस्म कर रहे हैं। दिलचस्प तथ्य सामने आया है कि हम मात्र पौने दो दिन की गैस का ही भंडारण कर सकते हैं। उसके लिए विशाखापट्टनम और मंगलुरु में ही मात्र दो भूमिगत भंडारण की गुफाएं हैं। देश की आबदी 147 करोड़ से अधिक और गैस भंडारण की मात्र दो गुफाएंङ्घ! कितने पराश्रित और अधूरे हैं हम! पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी आश्वस्त किया है कि रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं, लिहाजा 50 लाख एलपीजी सिलेंडर की रोजाना आपूर्ति की जा रही है। होटल, रेस्तरां वालों को वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। उससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा और प्रदूषण भी अधिक होगा, भारत उसका क्या जवाब देगा? भारत पेरिस संधि का एक सदस्य है और उसे तय समय-सीमा में उत्सर्जन कम करना है। बहरहाल मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन भारत में ऊर्जा-संकट साक्षात दिखाई दे रहा है। जगह-जगह लोग खाली सिलेंडरों के साथ घरों को लौट रहे हैं और गैस एजेंसियों के आगे लोगों की लंबी-लंबी कतारें दिख रही हैं। शहरी क्षेत्रों में समस्याएं ज्यादा आ रही हैं।

भूख के साथ पोषण की समस्या का भी हो निदान फंडिंग और नीतिगत प्रोत्साहन बेहद जरूरी

अधिक उपज वाली अनाज की आधुनिक किस्में पारंपरिक देसी फसलों की तुलना में क्या कम पौष्टिक होती हैं? यह एक आम धारणा है जो काफी हद तक सही है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में भी इस धारणा का समर्थन किया गया है। हरित क्रांति के बाद के शुरूआती कुछ दशकों में अ?धिक उपज वाली फसलों की किस्मों को मुख्य रूप से उपज बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था। उस समय अनाज की गुणवत्ता या पोषण तत्त्वों की परवाह नहीं की गई थी। मुख्य उद्देश्य संतुलित पोषण के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के बजाय खाद्य आपूर्ति बढ़ाकर व्यापक रूप से व्याप्त भूख को मिटाना था। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रचुर मात्रा में अनाज उपलब्ध होने और विश्व के अग्रणी अनाज निर्यातकों में से एक बनने के बावजूद, भारत में कुपोषण और अल्पपोषण की समस्या अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में ह्यगंभीर भूखङ्घ श्रेणी में 102वां स्थान दिया गया है। इस खराब स्थिति का कारण यह है कि पांच वर्ष से कम आयु के 32.9 फीसदी बच्चे बौनेपन (उम्र के हिसाब से कम कद) और 18.7 फीसदी बच्चे दुर्बलता (ऊंचाई के हिसाब से कम वजन) से ग्रस्त हैं। वयस्कों, विशेषकर महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में भी कुपोषण व्याप्त है। लगभग 12 फीसदी आबादी को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और लगभग दो-तिहाई लोगों को खाने के लिए स्वस्थ आहार नहीं मिलता।

कृषि वैज्ञानिकों ने पोषण संबंधी पहलू पर हाल के वर्षों में ही ध्यान देना शुरू किया है। फसल उत्पादकों ने अब मुख्य अनाजों की गुणवत्ता और पोषक तत्त्वों में सुधार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। पारंपरिक तरीके या जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जैव-संवर्धन वाली फसलें विकसित करने के प्रयास भी जारी हैं। इनमें स्वाभाविक रूप से आयरन, जिंक और विटामिन ए जैसे प्रमुख पोषक तत्त्वों की उच्च मात्रा पाई जाती है। चावल, गेहूं और मक्के जैसी व्यापक रूप से उपभोग की जाने वाली मुख्य फसलों सहित विभिन्न फसलों की 100 से अधिक उच्च उत्पादकता वाली जैव-संवर्धन किस्में, देश के विभिन्न हिस्सों में खेती के लिए जारी की जा चुकी हैं। उन्हें जिंक, आयरन, विटामिन और प्रोटीन जैसे आवश्यक पोषक तत्त्वों से समृद्ध किया गया है। हालांकि, अभी भी व्यापक रूप से उगाई जाने वाली कई फसलों की किस्में पौ?ष्टिकता के मामले में अपनी पुरानी किस्मों के बराबर नहीं हैं। फूड साइंस ऐंड न्यूट्रिशन (वॉल्यूम 13, अंक 2) के फरवरी 2025 अंक में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, गेहूं की आधुनिक किस्मों में जिंक, आयरन और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा, पुरानी किस्मों की तुलना में औसतन 19 से 28 फीसदी कम होती है। इस शोध पत्र में यह भी कहा गया है कि सामान्यतः प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ने के साथ-साथ अनाज की पौष्टिकता कम होती जाती है। रोगों और कीटों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता और कम जीवनकाल जैसी विशेषताओं वाली फसलों की किस्में विकसित करते समय अक्सर पोषण संबंधी पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), पश्चिम बंगाल के विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई एक अन्य रिपोर्ट में भी लगभग इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में मदद तो की है, लेकिन पोषण सुरक्षा की कीमत पर। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि चावल और गेहूं, जो भारत में लोगों की दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 फीसदी से अधिक पूरा करते हैं, पिछले लगभग 50 वर्षों में अपने पोषक तत्त्वों का 45 फीसदी तक खो चुके हैं। यह शोध पत्र 2023 में विज्ञान पत्रिका ह्यनेचरङ्घ (लेख संख्या 21164) में प्रकाशित हुआ था। इस शोधपत्र में एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी यह है कि हरित क्रांति के बाद विकसित की गईं उच्च उपज वाली किस्मों के अनाजों में पोषक तत्त्वों की मात्रा में गिरावट का कारण मिट्टी के बजाय पौधों से जुड़ा है। इन किस्मों के पौधे आम तौर पर मिट्टी से पर्याप्त पोषक तत्त्व ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह शोधपत्र यह भी दशार्ता है कि हाल ही में विकसित कुछ फसल किस्मों, विशेष रूप से चावल की किस्मों में आर्सेनिक जैसे कुछ विषैले तत्त्व पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बच्चों में एनीमिया और बौनेपन की उच्च दर का एक मुख्य कारण पॉलिश किए हुए चावल का बढ़ता सेवन है। चावल की पॉलिशिंग की प्रक्रिया में विटामिन, खनिज, फाइबर और फैटी एसिड जैसे कई उपयोगी तत्त्व नष्ट हो जाते हैं। पॉलिशिंग मुख्य रूप से बाजार में चावल की मांग बढ़ाने के लिए की जाती है। इन महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों की कमी से बच्चों में रुग्णता और मृत्यु दर भी अधिक होती है। सौभाग्य से, फसलों में पोषक तत्त्वों की कमी की समस्या से निपटने के लिए अब उत्पादन की नई तकनीकें उपलब्ध हैं। जैव संवर्धन के अलावा, जीन-संपादन तकनीक से पोषक तत्त्वों से भरपूर अ?धिक उपज वाली फसलें विकसित करना भी संभव हो गया है। हालांकि, आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के फसल उत्पादन कार्यक्रमों में ऐसी तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहायक नीतियों और पर्याप्त धन की आवश्यकता है। मूल रूप से, इन संस्थानों के अनुसंधान अवसंरचना और वित्तीय स्थिति को उन्नत करने की आवश्यकता है ताकि वे नई फसल किस्मों के अनाज की पोषक गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्पादन की अत्याधुनिक विधियों का उपयोग कर सकें। पोषक तत्त्वों से भरपूर फसल किस्मों के बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज कंपनियों और किसानों को इन बीजों का उपयोग करने के लिए उचित प्रोत्साहन भी दिए जाने चाहिए।

राशिफल

मेष राशि :- भाग्य का सितारा साथ देगा, बिगड़े कार्य बनेंगे, योजनापूर्ण अवश्य होंगे।

वृष राशि :- नवीन मैत्री व मंत्रणा सफल हो, संवेदनशील होने से बचिएगा।

मिथुन राशि :- स्त्रीवर्ग से हर्ष, कुछ चिन्ता, व्यवसायिक कार्यों में आरोप, कष्ट अवश्य होगा।

कर्क राशि :- व्यग्र मन उद्विघ्न रखेगा, कार्यगति मंद होवे किन्तु रुके कार्य निश्चय होवे।

सिंह राशि :- साधन संपन्नता के योग बने, दैनिक व्यवसाय गति अनुकूल बनी ही रहे।

कन्या राशि :- विरोधी परेशान करें, व्यर्थ धन का व्यय असमंजस की स्थिति होगी।

तुला राशि :- कार्य व्यवसाय में बाधा, तनाव क्लेश से बचने का प्रयास करें।

वृश्चिक राशि :- चिन्ता बनी रहेगी, कुटुम्ब की समस्याओं का समाधान होगा।

धनु राशि :- बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, आशानुकूल सफलता से सहयोग अवश्य ही बने।

मकर राशि :- स्थिति में सुधार कार्य सफलता से संतोष होगा, बिगड़े कार्य बनें।

कुंभ राशि :- स्वास्थ्य नरम एवं कही से तनाव पूर्ण वातावरण कष्टप्रद होगा।

मीन राशि :- दूसरो के कार्यों में समय और धन नष्ट न करें, समय का ध्यान दे।

गर्भवती महिलाएं भूलकर भी न खाएं ये फूड्स, एक्सपर्ट ने बताई चौंकाने वाली वजह

खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं को कटहल और पपीता जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को किन चीजों का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए।

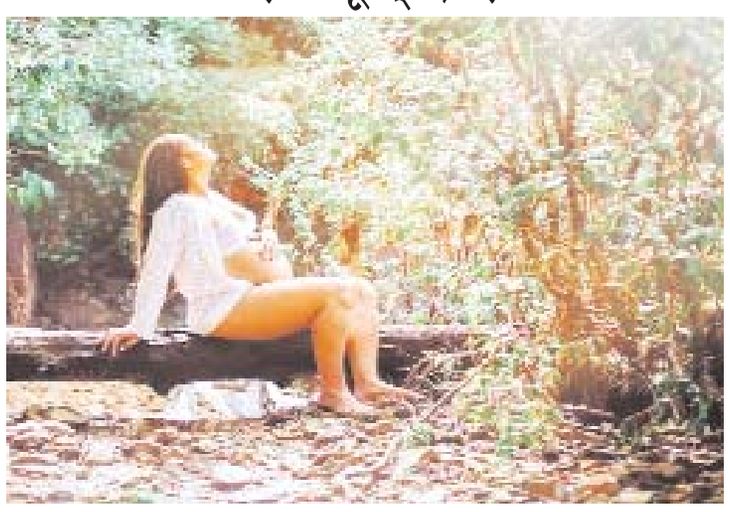

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को काफी सोच-समझकर डाइट प्लान दिया जाता है और कुछ चीजों को खाने की मनाही होती है। क्योंकि इसका सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है। इन चीजों के सेवन से गर्भपात की स्थिति बन सकती है। तो वहीं कुछ बार प्रेग्नेंट महिलाएं कुछ चीजें खा लेती हैं, जिसका बाद में उनको भारी नुकसान झेलना पड़ता है। बता दें कि प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को भूलकर भी कुछ फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीजों का सेवन करने से लेने के देने पड़ सकते हैं।

खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं को कटहल और पपीता जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को किन चीजों का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची के डाइटिशियन डॉक्टर प्रभास ने बताया, गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी पांच चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे. खासतौर पर पपीता व कटहल जैसी चीज का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए. अगर हम कटहल कहते हैं, तो कटहल का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ कटहल की सब्जी में ना खाए बल्कि, वह सब्जी के ग्रेवी में भी कटहल के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे में उसे भी ना खाए।

इन चीजों को न करें सेवन

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, कटहल और पपीता दोनों ही चीजों में लैक्टिक नामक एसिड पाया जाता है। इनमें पेपिन और लेटेक्स नाम के एंजाइम पाया जाता है, जोकि गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देता है। जिस कारण गर्भपात जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। कटहल खाने से एसिडिटी या फिर मल त्यागने में समस्या हो सकती है। क्योंकि कटहल में फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जोकि प्रेग्नेंसी के दौरान गैस की समस्या बन सकती है।

इसके अलावा प्रेग्नेंसी में भूलकर भी बाहर के पैकेट फूड या फिर कैंट फूड नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इनमें सोडियम और पाम तेल की मात्रा अधिक होती है। जोकि हाई ब्लड प्रेश? का कारण बन सकती है और बेचैनी हो सकती है। इन चीजों के सेवन से ब्लड पतला हो सकता है और डिलीवरी के समय कुछ परेशानी देखी जा सकती है। इसके साथ ही जंक फूड और खासतौर पर कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक में सोडा और पीएच लेवल काफी हाई होता है। जो बच्चे की स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें मौजूद हाई लेवल सोडा और पीएच वैल्यू गर्भपात की वजह बन सकता है।

इसलिए इन चीजों से प्रेग्नेंसी के दौरान दूर ही रहना चाहिए। खासतौर पर जो हाई फाइबर वाले फूड होते हैं, उनसे प्रेग्नेंसी के दौरान दूरी बनाकर रखना चाहिए। प्रयास करें कि ऐसी डाइट लें, जिसमें 90% पानी हो और पचाने में भी आसान हो।

जब हकीकत और फिल्म की कहानी मिल जाएं: अस्फारुल हक मामला बन गया द केरल स्टोरी 2

पुलिस ने एक शख़्स, जिसे अस्फारुल हक के रूप में पहचाना गया है, को कथित तस्करी और शोषण रैकेट के संबंध में गिरफ्तार किया है। जांचकताओं के अनुसार आरोपी पर महिलाओं के साथ दोस्ती करने के लिए झूठी पहचान का इस्तेमाल करने और बाद में उन्हें ब्लैकमेल और शोषित करने का शक है। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है। असल जिंदगी की यह घटना बिल्कुल विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड का आईना लगती है, जिसमें तीन हिंदू लड़कियों के साथ होने वाली गुप्त साजिश और शोषण की कहानी दिखाई गई है। जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे मासूम महिलाओं को धोखे और झूठी पहचान के माध्यम से फंसाया जाता है, वहीं अस्फारुल हक के मामले में भी महिलाओं को झूठी पहचान के जरिए दोस्ती कर ब्लैकमेल और शोषित करने का आरोप सामने आया है। यह हकीकत और फिल्म की कहानी के बीच चौंकाने वाला मेल दशार्ती है और यह दिखाती है कि कभी-कभी रील लाइफ और रियल लाइफ के बीच की दूरियां बेहद कम हो जाती हैं। इस बीच, फिल्म निमार्ता विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक कमाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित है और यह तीन हिंदू लड़कियों की डरावनी कहानी को उजागर करती है, जो अपने प्रेम संबंधों के माध्यम से धार्मिक परिवर्तन की गुप्त साजिश का सामना करती हैं। फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है और पहले से ही दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर रही है।

क्रिस्टन स्टीवट ने अमेरिका छोड़ने का बनाया मन, ट्रंप प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और ऑस्कर नॉमिनेटेड स्टार क्रिस्टन स्टीवर्ट ने अपने हालिया बयान से पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। 'ट्विलाइट' फेम अभिनेत्री ने खुलासा किया है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका (वर) छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। स्टीवर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान देश का राजनीतिक माहौल इतना अस्थिर हो गया है कि उनके लिए वहां स्वतंत्र रूप से काम करना नामुमकिन होता जा रहा है। द टाइम्स ऑफ लंदन से बात करते हुए,

ऑस्कर-नॉमिनेटेड स्टार ने माना कि वह अब अपने देश में सहज या क्रिएटिव रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह खुद को अमेरिका में रहते हुए देखती हैं, तो स्टीवर्ट ने सीधे जवाब दिया: "शायद नहीं।" उन्होंने आगे कहा, "मैं वहां आजादी से काम नहीं कर सकती," यह इशारा करते हुए कि उनकी निराशा राजनीति से आगे बढ़कर उनके प्रोफेशनल जीवन तक पहुंच गई है।

क्रिस्टन स्टीवर्ट अमेरिका क्यों छोड़ना चाहती हैं?

स्टीवर्ट के लिए, यह मुद्दा सिर्फ वैचारिक असहमति का नहीं है - यह रोजमर्रा की हकीकत के बारे में है। उन्होंने समझाया कि ट्रंप के दौर ने एक ऐसा माहौल बनाया है जो पाबंदी वाला और परेशान करने वाला लगता है, खासकर कलाकारों के लिए। उन्होंने कहा, "ट्रंप के तहत हकीकत पूरी तरह से टूट रही है," यह सुझाव देते हुए कि माहौल क्रिएटिव आजादी के लिए तेजी से प्रतिकूल हो गया है।

स्पेंसर एक्ट्रेस ने यह साफ कर दिया कि उनकी चिंताएं सिर्फ बेचैनी से कहीं ज्यादा हैं, यह इशारा करते हुए कि सांस्कृतिक बदलाव सीधे तौर पर अपनी शर्तों पर फिल्में बनाने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर रहा है।

वह इसके बजाय कहां जा सकती हैं?

यूरोप स्टीवर्ट के रडार पर मजबूती से दिख रहा है। उन्होंने ऐसी जगहों पर बसने की इच्छा के बारे में बात की जहां फिल्म निर्माण ज्यादा खुला और सहयोगी लगता है, यह कहते हुए कि वह "वह हकीकत बनाना चाहती हैं जिसमें हम रहना चाहते हैं"। एक्ट्रेस लंबे समय से इंडिपेंडेंट सिनेमा और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की ओर आकर्षित रही हैं, इसलिए यूरोप जाना एक स्वाभाविक अगला कदम होगा।

6661.90 क्विंटल धान में गड़बड़ी, किसानों के भुगतान के लिए 1.45 करोड़ रुपये अन्य समितियों से दिलवाए गए

ताखला कलां कांड पर विधानसभा तक गूंज, जिम्मेदार कौन?

धान खरीदी घोटाले की भरपाई 56 समितियों से!

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- जिले की ताखला कलां सहकारी समिति में धान खरीदी के दौरान सामने आए गबन और अनियमितताओं का बोझ अब जिले की 56 सहकारी समितियों पर डाल दिया गया है। किसानों के बकाया भुगतान के लिए करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि इन समितियों के धान कमीशन मद से कराई गई। मामला सामने आने के बाद अब यह मुद्दा प्रदेश की विधानसभा तक पहुंच गया है और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार मार्च 2024 में डिफाल्टर घोषित ताखलाकलां सहकारी समिति को ही धान उपार्जन का कार्य सौंप दिया गया था। उस समय जिला उपार्जन समिति में शामिल जिला सहकारी बैंक प्रबंधक के.के. सोनी, उपयुक्त सहकारिता पुष्पेंद्र कुशवाह और खाद्य विभाग के अधिकारी शैलेश मिश्रा के स्तर से खरीदी की जिम्मेदारी समिति को दी गई थी। धान खरीदी के दौरान समिति प्रबंधक सत्यनारायण बघेल द्वारा लगभग 90 किसानों की 6661.90 क्विंटल धान

में गड़बड़ी सामने आई। इस धान की कीमत करीब पौने दो करोड़ रुपये बताई गई। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने अरी थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धान से भरे दो ट्रक जब्त किए। बाद में जब्त धान की नीलामी कराई गई, जिससे 8 लाख 75 हजार 363 रुपये प्राप्त हुए और यह राशि किसानों को दी गई। इसके बावजूद किसानों का करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपये से अधिक का भुगतान बाकी रह गया था। किसानों का भुगतान कराने के लिए जिला उपार्जन समिति ने जिले की 56 सहकारी समितियों के धान कमीशन मद से राशि दिलवाई। हालांकि इन समितियों को यह राशि कब और कैसे वापस मिलेगी, इसको लेकर अब तक कोई स्पष्ट व्यवस्था सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले को लेकर बालाघाट विधायक मधु भगत ने विधानसभा में सवाल उठाया है। वहीं सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कहा है कि वे इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संज्ञान में लाकर जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे।

बड़े सवाल

डिफाल्टर समिति को धान खरीदी का काम क्यों दिया गया?

गड़बड़ी के बाद जिम्मेदारी किस अधिकारी की तय होगी?

56 समितियों से ली गई राशि वापस कब मिलेगी?

क्या पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी?

सब्जी मंडी में अव्यवस्था से जूझ रहे किसान, सड़क घेरकर लगी चिल्लर दुकानों से रोज लगता जाम

सिवनी जिला 31 जुलाई तक जल अभावग्रस्त घोषित, बिना अनुमति नलकूप खनन और जल दोहन पर प्रतिबंध

दैनिक रेवांचल टाईम्स, सिवनी। संभावित पेयजल संकट को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने संपूर्ण सिवनी जिले को 15 मार्च 2026 से 31 जुलाई 2026 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। यह आदेश म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित 2002) की धारा 3 के अंतर्गत जारी किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैंडपंपों का जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। भू-जल के अत्यधिक दोहन और निजी नलकूपों की अधिक गहराई तक खुदाई के कारण शासकीय पेयजल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट की आशंका जताई गई है। जारी आदेश के अनुसार सक्षम अनुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक जल स्रोत जैसे नदी, नाले, बंधान, स्टॉपडेम, जलाशय और सार्वजनिक कुओं से सिंचाई या औद्योगिक उपयोग के लिए पानी लेने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था नया नलकूप खनन नहीं करा सकेगी। नलजल योजनाओं से जल प्रदाय के दौरान घरों में मोटर पंप लगाकर प्रेशर से पानी खींचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसी स्थिति पाए जाने पर ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय मोटर पंप जब्त करने की कार्रवाई कर सकेंगे। जल संरक्षण और पेयजल के समुचित उपयोग के लिए ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को विशेष परिस्थितियों में नलकूप खनन, गहरीकरण अथवा साफ-सफाई की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 9 के तहत दो वर्ष तक का कारावास या दो हजार रुपये तक का जुमार्ना अथवा दोनों का प्रावधान है। यह आदेश 15 मार्च 2026 से 31 जुलाई 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

शिव पुराण ज्ञानयज्ञ सप्ताह का अंतिम दिवस संपन्न, आज हवन-पूजन व विशाल भंडारा

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी – नगर के मरझोर स्थित शिवनगर के शिव मंदिर परिसर में आयोजित श्री शिव पुराण ज्ञानयज्ञ सप्ताह के अंतिम दिवस की कथा में भगवान शिव की महिमा और उनकी भक्ति का महत्व बताया गया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान शिव अत्यंत भोले और दयालु हैं, वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उनके कष्टों को दूर कर देते हैं। कथा के दौरान बताया गया कि भगवान शिव सृष्टि के संहारक ही नहीं बल्कि कल्याणकारी भी हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। शिव पुराण हमें सत्य, करुणा, दया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कथा व्यास ने कहा कि जीवन में अहंकार का त्याग कर भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। शिव भक्ति से मनुष्य को आत्मिक शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण की कथा सुनने और उसका चिंतन करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। कथा के दौरान पत्रकारों सहित अन्य गणमान्य नागरिकों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर किसान मोर्चा के जिला महामंत्री शिव सनोडिया, वेद प्रकाश सूर्यवंशी, रमेश सनोडिया , पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन चंदेल, जिला पंचायत सदस्य घनश्याम सनोडिया, गणेश मंदिर के पुजारी पंडित हरि प्रसाद तिवारी, शिवदयाल सनोडिया , जी.एन. तिवारी, मानसिंह चंद्रवंशी, अखिलेश शिवहरे, अनिल दानोदिया, समिति अध्यक्ष राधेश्याम सनोडिया, कोषाध्यक्ष मनोज चंदेल, रेवाराम विश्वकर्मा, छविलाल तथा यजमान साधुलाल धुर्वे और सरस्वती धुर्वे सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजक समिति ने बताया कि कथा समापन के अवसर पर आज हवन-पूजन, पूणार्हुति एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्मलाभ लेने की अपील की गई है। पूरे कार्यक्रम के दौरान हर-हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा।

मंडी गेट से व्यापारियों की दुकानों तक रास्ता घिरा, किसानों को सुननी पड़ती खरी-खोटी; पानी, शौचालय और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी नदारद

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी – थोक सब्जी मंडी में किसानों को रोजाना कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर न तो मंडी प्रशासन गंभीर दिखाई दे रहा है और न ही पक्ष-विपक्ष के जनप्रतिनिधि। किसान अपनी उपज लेकर मंडी तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझना पड़ता है। मंडी परिसर में किसानों के लिए स्वच्छ पानी तक की समुचित व्यवस्था नहीं है और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। मंडी गेट से लेकर व्यापारियों की दुकानों तक माल ले जाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संकरी व्यवस्था के कारण यहां अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे किसानों और व्यापारियों दोनों को परेशानी होती है। वहीं मंडी प्रशासन की लापरवाही के कारण मंडी गेट से लेकर व्यापारियों की दुकानों तक का रास्ता चिल्लर सब्जी मंडी वालों ने घेर रखा है। दोनों ओर से चिल्लर दुकानदार अपनी दुकानें और सामान सड़क तक फैला लेते हैं, जबकि यही रास्ता व्यापारियों की गाड़ियों और किसानों की गाड़ियों के आवागमन का मुख्य मार्ग है। इन चिल्लर सब्जी दुकानों में खरीददारों की भीड़ भी इतनी बढ़ जाती है कि रास्ते से आना-जाना दुश्वार हो जाता है। कई बार यहां 10 से 15 मिनट तक का जाम भी लगा हुआ नजर आता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी चिल्लर दुकानदार के सामान में हल्का सा धक्का भी लग जाए तो तुरंत किसानों के साथ विवाद की स्थिति बन जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जी लेकर आने वाले किसानों को कई बार इन दुकानदारों की खरी-खोटी भी सुननी पड़ती है, लेकिन विवाद से बचने के लिए किसान चुपचाप सब सहने को मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा मंडी में किसानों के लिए न तो पार्किंग की समुचित व्यवस्था है और न ही बैठने की कोई सुविधा। किसान घंटों अपनी उपज के साथ मंडी में खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नजर नहीं आता।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि

जब सब्जी मंडी किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई है, तो फिर किसानों को ही यहां मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं। प्रशासन से लेकर पक्ष-विपक्ष के नेता और छोटे-बड़े जनप्रतिनिधि अक्सर फोटो खिंचवाने के लिए मौके पर पहुंच जाते हैं, लेकिन किसानों की इन वास्तविक समस्याओं को लेकर कभी कोई ठोस आवाज क्यों नहीं उठाई जाती–यह सवाल अब किसानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

स्कूलों में शौचालय निर्माण में बड़ा खेल! भाजपा नेता पर अनियमितताओं के आरोप

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी – जिले के शासकीय स्कूलों में शौचालय निर्माण कार्य को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य में नियमों को दरकिनार कर मनमानी तरीके से काम कराया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए जारी राशि और वास्तविक निर्माण कार्य के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। कई स्थानों पर अधूरे निर्माण, घटिया सामग्री के उपयोग और बिना मानक के काम किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले में एक भाजपा नेता की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, जो निर्माण कार्य में हस्तक्षेप कर अपने चहेते लोगों से काम करवा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का भी तालमेल सेट होने की चर्चा क्षेत्र में चल रही है, जिसके चलते शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों में बच्चों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे शौचालय यदि सही तरीके से नहीं बनेंगे तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ेगा। कई जगहों पर निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है तो कहीं गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले को लेकर लोगों ने प्रशासन से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो शासकीय राशि का दुरुपयोग होता रहेगा और स्कूलों में सुविधाएं भी अधूरी रह जाएंगी।

5 हजार के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा और एसडीओपी सचिन परते के मार्गदर्शन में जिले में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना बंडोल पुलिस ने चोरी के दो प्रकरणों में फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार थाना बंडोल में दर्ज अपराध क्रमांक 16/26 धारा 331(4), 305 (ए) बीएनएस में 3 हजार रुपये तथा अपराध क्रमांक 429/25 धारा 331(4), 305 (ए) बीएनएस में 2 हजार रुपये का इनाम घोषित था। दोनों प्रकरणों में फरार चल रहे आरोपी विकास पिता मनीराम डेहरिया (29 वर्ष) निवासी निवारी चौकी बादलपार थाना कुरई, हाल निवासी जनता नगर टपरा मोहल्ला थाना डूण्डा सिवनी को पुलिस ने 14 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन चोरी करने वाला अपराधी है और थाना डूण्डा सिवनी का निगरानी बदमाश भी है। उसके खिलाफ थाना अरी, लखनवाड़ा और डूण्डा सिवनी में चोरी सहित अन्य अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सिवनी में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

भाजपा जिला कार्यालय में प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा की अध्यक्षता में जिला प्रबंध समिति की बैठक

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- भाजपा जिला कार्यालय में जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की अध्यक्षता में जिला प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन, जिला के संगठन प्रभारी एवं जबलपुर केंट विधायक अशोक रोहाणी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, बरघाट विधायक कमल मर्सकोले, पूर्व जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, कटनी जिला के प्रभारी सुजीत जैन तथा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डेहरिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के पश्चात भाजपा कार्यालय में प्रभारी मंत्री ने कार्यकताओं से चर्चा की। इस दौरान जिले के व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिस पर मंत्री द्वारा जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बैठक से पूर्व भाजपा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल, गजानंद पंचेश्वर और मुकेश बघेल ने सर्किट हाउस पहुंचकर प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा का स्वागत किया तथा उन्हें जिले में चल रही संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी।

कार्यालय ग्राम पंचायत बंडोल
जनपद पंचायत सिवनी,जिला सिवनी (म.प्र.)

क्र./38/पंचा./2026 दिनांक 11/03/26

निविदा आमंत्रण

ग्राम पंचायत बंडोल के वर्ष 2026-27 के समस्त योजनाओं के पक्के एवं कच्चे निर्माण कार्यों के लिए सामग्री सीमेंट,रेट,गिट्टी 20एम एम , 40 एम एम, लोहा 8, एम एम,12 एम एम, मुरम, ईंट, सीमेंट पाईप 600 एम एम एवं 1000 एम एम,नल जल योजना सामाग्री, स्वच्छता सामग्री, फर्नीचर,पानी टेंकर, परिवहन हेतु ट्रैक्टर किराया, सेटिंग किराया, सांसद विधायक निधि से प्राप्त राशि आदि निर्माण कार्यों एवं मरम्मत में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की आवश्यकता है। अतः फर्मों से कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं इच्छुक फर्म दिनांक 12 मार्च2026 से 18 मार्च 2026 तक कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनो को छोड़कर निविदा बंद लिफाफा में जमा कर सकते हैं।

श्रीमती सियवती कृष्ण कुमार उइके सरपंच — धानसिंह (धन्नू) बघेल उपसरपंच

सचिव - सुखलाल जंघेला — रोज.सहा- ...राजेश दर्शनिया

कार्यालय ग्राम पंचायत कलारबांकी
जनपद पंचायत सिवनी,जिला सिवनी (म.प्र.)

क्र./ /पंचा./2026 दिनांक 14/03/2026

साप्ताहिक बैठकी बाजार ठेका नीलामी सूचना वर्ष (2026-27)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कलारबांकी में साप्ताहिक बैठकी बाजार ठेका की नीलामी वर्ष (2026-27) 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए दिनांक 18/03/2026 दिन बुधवार को समय दोपहर 1:00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत कलारबांकी में रखी गई है। बोली कर्ता के द्वारा बोली के पूर्व समय 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाजार नीलामी हेतु अमानत राशि 48000=00 रू. (अड़तालीस हजार रुपए) नगद जमा करना होगा` नियम व शर्ते कार्यालय ग्राम पंचायत कलारबांकी के सूचना पटल पर देख सकते है।

टीप- आफसेट प्राईस :-4,77,220 =00 रू. (चार लाख सतहत्तर हजार दो सौ बीस रुपये)

नोट- पूर्व की बाजार ठेके की बकाया राशि बकायादार ठेकेदार एवं उनके वसूली कर्ता नीलामी में भाग नहीं ले सकते

श्रीमति पिंकी भरत इनवाती सरपंच — श्रीमति अंजू प्रदीप राय उपसरपंच

सचिव - अर्चना विश्वकर्मा, — रोज.सहा- ...

कार्यालय ग्राम पंचायत कलारबांकी
जनपद पंचायत सिवनी,जिला सिवनी (म.प्र.)

क्र./ /पंचा./2026 दिनांक 14/03/2026

साप्ताहिक बैठकी बाजार ठेका नीलामी सूचना वर्ष (2026-27)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कलारबांकी में साप्ताहिक बैठकी बाजार ठेका की नीलामी वर्ष (2026-27) 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए दिनांक 18/03/2026 दिन बुधवार को समय दोपहर 1:00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत कलारबांकी में रखी गई है। बोली कर्ता के द्वारा बोली के पूर्व समय 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाजार नीलामी हेतु अमानत राशि 48000=00 रू. (अड़तालीस हजार रुपए) नगद जमा करना होगा` नियम व शर्ते कार्यालय ग्राम पंचायत कलारबांकी के सूचना पटल पर देख सकते है।

टीप- आफसेट प्राईस :-4,77,220 =00 रू. (चार लाख सतहत्तर हजार दो सौ बीस रुपये) नोट- पूर्व की बाजार ठेके की बकाया राशि बकायादार ठेकेदार एवं उनके वसूली कर्ता नीलामी में भाग नहीं ले सकते

श्रीमति पिंकी भरत इनवाती सरपंच — श्रीमति अंजू प्रदीप राय उपसरपंच

सचिव - अर्चना विश्वकर्मा, — रोज.सहा- ...

कार्यालय ग्राम पंचायत बंडोल
जनपद पंचायत सिवनी,जिला सिवनी (म.प्र.)

क्र.37/पंचा./ज.पं./ बाजार नीलामी2026 दिनांक 11/03/2026

साप्ताहिक बैठकी बाजार ठेका नीलामी सूचना वर्ष (2026-27)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बंडोल में साप्ताहिक बैठकी बाजार की नीलामी वर्ष (2026-27) 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए दिनांक 18/03/2026 दिन बुधवार को समय दोपहर 12:00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत (सामुदायिक भवन) बंडोल में रखी गई है। बोली कर्ता के द्वारा बोली के पूर्व बाजार नीलामी हेतु अमानत 100000 (एक लाख रुपए) नगद जमा करना होगा` नियम व शर्ते कार्यालय ग्राम पंचायत बंडोल के सूचना पटल पर देख सकते है ।

टीप- आफसेट प्राईस :- 13,57,877(तेरह लाख संतावन हजार आठ सौ सत्तर रुपये)

श्रीमती सियवती कृष्ण कुमार उइके सरपंच — धानसिंह (धन्नू) बघेल उपसरपंच

सचिव - सुखलाल जंघेला — रोज.सहा- ...राजेश दर्शनिया

दक्षिण के द्वार नेपानगर को बनायेंगे प्रदेश के विकास का प्रमुख द्वार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नेपानगर अद्भुत नगरी है। यह कृषि और उद्योग का बेजोड़ संगम है। बुरहानपुर जिला मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का जीवंत उदाहरण है। हम बुरहानपुर के एग्री एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग का हब बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदेश के जनजातीय वर्ग का समग्र विकास हमेशा से ही हमारी पहली प्राथमिकता रही है। जनजातीय समाज के समग्र कल्याण के लिए नए वित्त वर्ष 2026-27 के सालाना बजट में 26 प्रतिशत की वृद्धि कर 47 हजार 428 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है, जिससे जनजातीय वर्ग के चहुंमुखी विकास और कल्याण में कोई कमी न रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय पीएम जन-मन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत कराए जा रहे कार्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण का नया अध्याय लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को बुरहानपुर जिले के जनजातीय बहुल नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनजातीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा क्षेत्र को 363 करोड़ 82 लाख रुपए के 127 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 191 करोड़ 62 लाख रुपए लागत के 81 विकास कार्यों का भूमिपूजन (30.59 करोड़ से सातपायरी में औद्योगिक प्रक्षेत्र के भूमिपूजन सहित) और 172 करोड़ 20 लाख रुपए लागत के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकास तभी सार्थक है, जब इसके प्रकाश का पूरा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन विकास कार्यों की सौगात मिली है, यह इस क्षेत्र के जनजातीय बंधुओं के कल्याण में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इतिहास के पन्नों में नेपानगर दक्षिण के द्वार के रूप में अंकित है। कभी खानदेश और दक्षिण की काशी के रूप में पहचाने जाने वाले नेपानगर को हमारी सरकार महाराष्ट्र के छोर पर मध्यप्रदेश के विकास के प्रमुख द्वार के रूप में विकसित करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं (झिरमिट्टी मध्यम सिंचाई परियोजना एवं नावथा वृहद सिंचाई परियोजना) को शासकीय मंजूरी मिलने की जानकारी देते हुए कहा कि ये सिंचाई परियोजनाएं इस क्षेत्र के 34 हजार 400 किसान परिवारों की तकदीर और तस्वीर बदल देंगी। उन्होंने बताया कि कुल 2598.97 करोड़ रुपये की इन दोनों परियोजनाओं से जनजातीय बहुल क्षेत्र में 51800 हेक्टेयर कृषि रकबे में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इन परियोजनाओं से 132 गांव लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी के भी अनर्गल प्रलाप से कतई प्रभावित न हों। इन परियोजनाओं के निर्माण में हमारी सरकार किसी भी व्यक्ति या किसान को घर से बेघर नहीं होने देगी। हम सबके हितों का बराबर ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नेपानगर पेपर मिल इस क्षेत्र की पहचान है। यह मिल हमेशा की तरह चलती रहेगी। इस चलाए रखने के लिए हम सभी व्यवस्थाएं और समुचित प्रबंधन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस मिल के कागज भी खरीदेगी और श्रमिक को उसके रोजगार से जोडे. रखेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रमुख घोषणाएँ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बीते एक माह के दौरान ही दो कार्यक्रमों में बुरहानपुर जिले को करीब 1100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें मिली हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुरहानपुर के शासकीय महाविद्यालय में कृषि संकाय की पढ़ाई प्रारंभ कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपानगर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की स्मृति में एक आकर्षक उद्यान बनाया जाएगा। धूलकोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रोन्नत किया जाएगा। लोखंडिया से हसीनाबाद मार्ग के चौड़ीकरण के साथ ताप्ती नदी पर वर्तमान रपटे के स्थान पर एक उच्च स्तरीय पुल बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की पहचान असीरगढ़ के किले को भव्य पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के वनवासियों को दिए गए वन अधिकार पट्टों को अब राजस्व विभाग के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्री के रूप में बदला जाएगा, इसकी रजिस्ट्री शुल्क का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। क्षेत्रीय जनजातीय बन्धुओं को वनाधिकार पट्टों का लाभ देने के लिए जल्द ही पुनः सर्वे कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि, बागवानी और मसाला उत्पादन के लिए मशहूर निमाड़ क्षेत्र में सभी प्रकार की फसलों का बीमा कराने और इस क्षेत्र में शीघ्र ही रीजनल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने की बात कही।

सिंचाई क्षमता में लगातार हो रही वृद्धि : मंत्री सिलावट

जल संसाधन मंत्री एवं बुरहानपुर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सिंचाई क्षमता में लगातार दिन दूनी-रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए मंजूर दो सिंचाई परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह परियोजना जनजातीय क्षेत्र के विकास की नई इबारत लिखेंगी। उन्होंने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना भी मंजूर हो चुकी है। इससे नेपानगर सहित बुरहानपुर जिले की सिंचाई क्षमता में भारी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 54 लाख हैक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई हो रही है, जिसे वर्ष 2029 तक बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर तक किया जाएगा। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि नेपानगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में यहां की नेपा मिल का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से अनुरोध किया कि यह नेपा मिल किसी भी स्थिति में बंद न हो, बल्कि हमेशा की तरह संचालित होती रहे, ऐसे सभी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान, मजदूर, विद्यार्थी और महिला सहित समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए पूरी शिद्धत से काम कर रही है। विधायक बुरहानपुर एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। उन्होंने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जाने एवं 19 मार्च से प्रारंभ हो रहे राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकार, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सरकार है। सरकार के प्रयासों से प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बुरहानपुर में "सम्राट विक्रमादित्य" महानाट्य का मंचन कराने का अनुरोध किया। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुमंजू राजेन्द्र दादू ने जनजातीय उत्सव के प्रतीक मांदल और झांझर की उल्लसित झनकार के बीच मुख्यमंत्री डॉ. यादव को तीर कमान भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का दूरस्थ एवं सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र होने से नेपानगर क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने असीरगढ़ के प्राचीन किले का जीर्णोद्धार करवाने एवं यहां पर्यटन गतिविधियां विकसित करने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाराम मार्को, उपाध्यक्ष गजानंद, नगर निगम बुरहानपुर की महापौर माधुरी अतुल पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, जनजातीय बंधु, किसान और महिलाएं उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन कन्या-पूजन एवं भगवान बिरसा मुंडा जी के चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर लगी विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में कृषक कल्याण वर्ष के तहत किये जा रहे नवाचारों और प्रयासों को दशार्या गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसकी सराहना की।

पक्षाल जैन के आलीराजपुर आगमन पर ऐतिहासिक स्वागत, विशाल चल समारोह के साथ हुआ सार्वजनिक अभिनंदन

आलीराजपुर । संघ लोक सेवा आयोग (**UPSC**) परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त कर ऑल इंडिया स्तर पर उत्कृष्ट रैंक हासिल करने वाले होनहार युवा पक्षाल सेक्रेटरी जैन के प्रथम आलीराजपुर आगमन पर नगर में भव्य, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्वागत किया गया। इस अवसर पर शहर में विशाल चल समारोह निकाला गया तथा बाद में सार्वजनिक अभिनंदन समारोह आयोजित कर उनका सम्मान किया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं अधिवक्ता रहे स्वर्गीय प्रकाशचन्द्र जैन की नातिन दीप्ति सेक्रेटरी (बाग) के सुपुत्र तथा आलीराजपुर के परमार्थ मेडिकल स्टोर के संचालक राहुल जैन (लक्की) और मनीष जैन (नानपुर) के भांजे पाक्षाल जैन की इस उपलब्धि पर पूरे नगर में उत्साह का वातावरण देखने को मिला। शाम लगभग 5 बजे बस स्टैंड से भव्य चल समारोह प्रारंभ हुआ, जो एम.जी. रोड से होते हुए राहुल जैन (लक्की) के निवास तक पहुँचा। इस दौरान पक्षाल जैन खुली गाड़ी में सवार होकर नागरिकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। रास्ते में जगह-जगह नागरिकों ने पुष्पमालाओं और फूलों की वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। चल समारोह में महिलाएँ, युवतियाँ और युवा नृत्य व गरबा करते हुए शामिल हुए, वहीं देशभक्ति गीतों की गूंज से पूरा वातावरण उत्साह से भर उठा। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। मार्ग में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मकु परवाल के निवास पर सांसद अनिता चौहान ने भी पाक्षाल जैन का स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएँ दीं। इसके पश्चात सोरवा रोड स्थित मां वाटिका गार्डन में प्रकाशचन्द्र जैन परिवार द्वारा भव्य अभिनंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मंच पर पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदोरिया, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेश पटेल, भारतीय पत्रकार संघ 'एआईजे' के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जागरूक नागरिक मंच के अध्यक्ष विक्रम सेन, जैन तीर्थ लक्ष्मणी के अध्यक्ष कमल जैन, जयस जिलाध्यक्ष अरविंद कनेश, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओमप्रकाश राठौड़, श्री संघ जैन समाज अध्यक्ष मनीष जैन, गोविंद कापड़िया, जवाहर कोठारी सहित पाक्षाल के पिता निलेश सेक्रेटरी उपस्थित रहे। समारोह में सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में पक्षाल जैन एवं उनके परिवार को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायी बताया। अपने उद्बोधन में पक्षाल जैन ने कहा कि उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी विद्यालय से की और उनके नानाजी स्वर्गीय प्रकाशचन्द्र जैन का सपना था कि वे आईएएस बनें। उन्होंने कहा कि नानाजी के आशीर्वाद और माता-पिता के सहयोग से ही वे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि बड़ा सपना देखना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अध्ययन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और जीवन को सुरक्षित बनाना है तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। पक्षाल जैन ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता दीप्ति सेक्रेटरी, पिता निलेश सेक्रेटरी तथा छोटी बहन क्रिया सेक्रेटरी को दिया। इस अवसर पर उनकी माता दीप्ति सेक्रेटरी ने कहा कि पाक्षाल ने अपनी पढ़ाई के दौरान मोबाइल का त्याग किया, खान-पान की परवाह किए बिना लगातार अध्ययन किया और यहां तक कि पारिवारिक आयोजनों में भी शामिल नहीं हुए। उनकी मेहनत और समर्पण के कारण ही आज यह सफलता संभव हो सकी। वहीं उनकी छोटी बहन क्रिया सेक्रेटरी ने कहा कि वह भी अपने भाई से प्रेरणा लेकर पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहती हैं और भविष्य में उनसे भी बेहतर उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य रखती हैं। कार्यक्रम का संचालन मोनिका जैन ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन राहुल जैन (लक्की) एवं रिया जैन ने किया। मीडिया प्रभारी कृष्णकांत बेड़िया के अनुसार इस अवसर पर जैन समाज सहित आलीराजपुर के विभिन्न समाजों के गणमान्य नागरिक, महिलाएँ और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

अध्ययन भ्रमण विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने, सीखने का सुअवसर : राज्यपाल पटेल

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि अध्ययन भ्रमण आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक समन्वय और संसाधन प्रबंधन के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का अवसर होता है। अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे भ्रमण के दौरान समझने और सीखने का प्रयास करें। प्रतिदिन भ्रमण के अंत में दिनभर की गतिविधियों और अनुभवों का चिंतन करें। भ्रमण टीप का अभिलेखन करें।

राज्यपाल पटेल रविवार को लोकभवन में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली में अध्ययनरत वरिष्ठ सैन्य एवं सिविल अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। दल 15 से 21 मार्च तक मध्यप्रदेश के अध्ययन भ्रमण आया है। कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि भ्रमण नये अनुभवों, सामाजिक विशिष्टताओं, आध्यात्मिक आस्था और विकास के विभिन्न आयामों को देखने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का सुअवसर होता है। विगत दिनों बौद्ध अवशेषों को कोलंबो, श्रीलंका से वापस भारत लाने की उनकी यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीलंका में 7 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित पवित्र अवशेषों का 14 लाख लोगों ने दर्शन किया। प्रदर्शन के आखिरी दिन सारी रात लाखोंश्रद्धालुओं ने लाइन लगाकर दर्शन किए। आस्था के प्रति समर्पण और आध्यात्मिकता का उनके लिए यह अद्भुत अनुभव रहा है।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक क्षेत्रों में आई क्रांतिकारी प्रगति, वास्तव में 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के विराट स्वरूप को समझने का सुअवसर है।जरूरी है कि आप प्रशासनिक ढांचे, विकास योजनाओं तथा सामाजिक-आर्थिक प्रगति के विभिन्न आयामों को नजदीक से देखे उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों, की महत्ता का अनुभव करें।उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य की धरती आदिम सभ्यता, प्राचीन भारत की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत स्वरूप है।यहां कि विश्व धरोहर सांची स्तूप, भीमबेटका और खजुराहों, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे पवित्र स्थल हमारे गौरवशाली इतिहास के साक्षी है। भ्रमण अवसर पर ग्रामीण विकास, शहरी प्रबंधन, पर्यटन संवर्धन तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के मॉडल में जन सहभागिता की भूमिका और महत्व को भी जानने का प्रयास करें। उज्जैन और इंदौर जैसे शहरों में बड़े आयोजनों में प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और औद्योगिक विकास के मॉडल का गहन अध्ययन जरूर करें।कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल को प्रशासन अकादमी और राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। राज्यपाल ने भ्रमण दल के प्रमुख मेजर जनरल पवन पाल सिंह को गोंड कला की पेटिंग भेंट की। आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के संचालक मुजीबुर्रहमान खान ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में 47 सप्ताह के पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकारियों में से 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल प्रदेश प्रवास पर आया है।उन्होंने बताया कि अध्ययन दल प्रदेश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेगा। उनको राज्य के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, स्थलों औद्योगिक प्रगति, विभिन्न नवाचारों और प्रबंधकीय व्यवस्थाओं से रू-ब-रू कराया जाएगा।

घरेलू गैस सिलेंडर समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश

भोपाल। अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर समय पर उपलब्ध कराने तथा एजेंसियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने भी अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा के निर्देश दिए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रेस ब्रीफ जारी कर नागरिकों से पैनिक बुकिंग नही करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में एजेंसी पर जाकर बुकिंग करने के स्थान पर डिजिटल माध्यम से बुकिंग करने की सलाह दी गयी है। ऑयल कंपनियों द्वारा मोबाइल एप, एसएमएस, व्हाट्सएप तथा आईवीआरएस कॉल द्वारा गैस बुकिंग की सुविधा प्रदान की गयी है अतःउपभोक्ता बुकिंग के लिए इन डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें। देश में घरेलू गैस के उत्पादन में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसके अलावा स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज से एलपीजी के दो शिप भारत के लिए रवाना हो गए हैं, जो 16-17 मार्च तक भारत के कांडला (गुजरात) और मुंद्रा पोर्ट (मुंबई) पर पहुँच जायेंगे।

1357 सिलेंडर जप्त

एलपीजी की कालाबाजारी तथा जमाखोरी के विरूद्ध जारी निदेर्शों के पालन में प्रदेश भर में लगातार कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में 1025 स्थानों पर कार्यवाही कर 1357 सिलेंडर जब्त किये गए तथा 08 प्रकरण में एफआईआर की गयी। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी तथा घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता के सम्बन्ध में ऑयल कंपनियों से समन्वय के लिए राज्य स्तर पर 6 सदस्यीय समिति भी गठित की गयी है, जो प्रदेश में कामर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी करेगी। पीएनजी गैस का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से अपील की गयी है कि वह अनावश्यक रूप से एलपीजी गैस बुकिंग नहीं करें। पेट्रोल, डीजल ,घरेलू पीएनजी तथा सीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और इनकी आपूर्ति भी निरंतर एवं बिना कटौती के जारी रहेगी। गैस एजेंसियों के संचालन, सिलेंडर वितरण की समयबद्धता और उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है। समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए है कि यदि कहीं वितरण व्यवस्था में अनियमितता या विलंब की शिकायत मिलती है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए। जिला प्रशासन गलत सूचनाओं का प्रसार और अफवाहों को सख्ती से रोकें और उपभोक्ताओं तक मीडिया के माध्यम से सही सूचना पहुंचाएं। नागरिकों के बीच सकारात्मक माहौल बनाए और सूचना-तंत्र मजबूत कर अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें। ऑयल कंपनी के स्टेट नोडल ऑफिसर श्री अजय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में गैस सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक है तथा प्रदेश के 11 बॉटलिंग प्लांट एवं वितरकों के गोदाम में पर्याप्त सिलेण्डर उपलब्ध हैं। घरेलू उपभोक्ताओं से अपील की गयी है कि विगत अंतिम रिफिल के 25 दिन बाद पुनः बुकिंग करायें। प्रशासन द्वारा वाणिज्यिक उपयोगकताओं को उपलब्ध स्टॉक का विवेकपूर्ण उपयोग करने एवं वैकल्पिक ईंधन स्त्रोतों को अपनाने की सलाह भी दी गयी है। जहां पीएनजी लाइन उपलब्ध है वहां पीएनजी के कनेक्शन लेने और जिन कामो में गैस ज्यादा खर्च होती है उनको नियंत्रित करने एवं विकल्प तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रदेश में घरेलू गैस की पर्याप्त आपूर्ति जारी है, उपभोक्ता अनावश्यक रूप से अफवाहों से भ्रमित न हों। देश की रिफायनरी उच्च क्षमता पर कार्य कर रही हैं तथा पश्चिम एशिया के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

सशक्त एवं जागरूक उपभोक्ता ही मजबूत अर्थ व्यवस्था की नींव : खाद्य मंत्री राजपूत

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने सभी को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि एक सशक्त और जागरूक उपभोक्ता ही मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव होता है। राजपूत ने कहा कि खाद्य पदार्थों के रूप में धीमा जहर देने वाले के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करें, तभी इस दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है इसलिए उसके अधिकारों की रक्षा करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और उचित मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हो, यह हमारा दायित्व भी है और संकल्प भी है। मंत्री राजपूत ने कहा कि खरीददारी करते समय बिल लेना, उत्पाद की गुणवत्ता और समाप्ति की तिथि अवश्य देखना, किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराना, यह सभी जागरूक उपभोक्ता को मजबूत बनाते हैं। उपभोक्ताओं के हित में भारत सरकार ने वर्ष 2019 में नया उपभोक्ता

संरक्षण अधिनियम बनाया। यह कानून उपभोक्ताओं के रक्षा की गारंटी देता है। इसमें 06 प्रकार के अधिकार चुनने का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, उपभोक्ताओं की सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता की समस्याओं के निराकरण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार (जागरूक बने रहने का अधिकार) बताये गये हैं। राजपूत ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध हैं। भ्रामक खबरों से सावधान रहें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वर्तमान परिस्थितियों में बड़े आयोजनों से बचें।

जिद्दी उपभोक्ता बनें

मंत्री राजपूत ने कहा कि अपने अधिकारों के लिये उपभोक्ताओं को जिद करना चाहिये। ठगी होने पर उपभोक्ताओं को उपभोक्ता न्यायालयों की मदद लेनी चाहिए और इस संबंध में दूसरों को भी जागरूक करना चाहिये। उन्होंने इस संबंध में एक घटना का उल्लेख करते हुए सागर के डॉक्टर हरिसिंह गौर को भी याद किया। राजपूत ने कहा कि मेरा आग्रह है कि हम सभी उपभोक्ता हैं तथा हम सभी का यह कर्तव्य है कि अनुचित व्यापार को रोकने में अपनी जागरूकता का परिचय दें एवं ठगे जाने से बचें। उपभोक्ता कानून में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का प्रावधान है। सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भी की जाती है। जिला आयोग/फोरम के निर्णय से असंतुष्ट होने पर राज्य आयोग में अपील का भी प्रावधान है। नापतौल में कमी मिलने पर कोई भी उपभोक्ता नापतौल कार्यालय एवं आयोग में शिकायत कर सकता है।

52 हजार से अधिक किसानों ने गेहूं उपार्जन हेतु कराया पंजीयन

जिले में 7 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीदी

दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तिथि में संशोधन किया गया है। अब जिले में गेहूं की खरीदी 7 अप्रैल से शुरू होगी। गेहूं उपार्जन का कार्य सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक (शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर) किया जाएगा। समर्थन मूल ?य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 7 फरवरी से शुरू हुए पंजीयन प्रक्रिया में कटनी जिले के 52 हजार 951 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 55 पंजीयन केंद्र बनाए गए थे।

पंजीयन में बहोरीबंद अग्रणी

समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु तहसील बहोरीबंद में 10 हजार 826, ढीमरखेड़ा में 9 हजार 748 और विजयराघवगढ़ में 6 हजार 780 किसानों ने पंजीयन कराया है। इसी प्रकार तहसील रीठी में 5 हजार 411, बड़वारा में 5 हजार 43 और बरही में 4 हजार 87 किसानों ने पंजीयन कराया है। इसके अलावा तहसील कटनी नगर में 2 हजार 951 व कटनी में 2 हजार 778 किसनों ने अपना पंजीयन कराया है। इस वर्ष 2 हजार 625 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसानों से गेहूँ का उपार्जन किया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2 हजार 585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रुपए अधिक है। वहीं म.प्र. सरकार द्वारा 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।

उपार्जित फसल के भुगतान हेतु बैंक खाता

किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा।

चना और मसूर खरीदी के लिये पंजीयन की अंतिम तिथि 16 मार्च

रबी वर्ष 2025-26 (विपणन वर्ष 2026-27) में समर्थन मूल्य के तहत ई-उपार्जन पोर्टल पर चना एवं मसूर के पंजीयन की अंतिम तिथि 16 मार्च है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले में गेहूँ पंजीयन के लिए निर्धारित 55 पंजीयन केन्द्रों में ही चना एवं मसूर के उपार्जन हेतु भी पंजीयन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री तिवारी ने सभी किसानों से निर्धारित समय में अपना पंजीयन कराने की अपील की है।

इस वर्ष चेहरे से होगा किसान का सत्यापन

चना एवं मसूर के पंजीयन के दौरान इस वर्ष खरीदी केन्द्रों द्वारा उपज खरीदने से पहले कृषकों की वास्तविक पहचान के लिए आधार का सत्यापन सक्षम पी.ओ.एस. मशीन या मोबाईल ऐप के माध्यम से चेहरे का प्रमाणीकरण कर वास्तविक किसान का सत्यापन किया जावेगा, क्योकि विगत वर्षों की भांति ओ.टी.पी मान्य नहीं होगा।

किसान की अनुपस्थिति में 3 लोग हो सकेंगे अधिकृत

यदि कृषक खरीदी केन्द्र पर स्वयं उपस्थित न हो पाये तो अपनी फसल के विक्रय हेतु पंजीयन के समय 3 अधिकृत व्यक्तियों का नाम और आधार नंबर दे सकता है। जिनके द्वारा पंजीकृत किसान की फसल खरीदी केन्द्र पर लाई जा कर विक्रय किया जा सकेगा। कृषक द्वारा अधिकृत किये गये व्यक्तियों का भी आधार-सक्षम पी.ओ.एस. मशीन या मोबाईल ऐप के माध्यम से चेहरे का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति अधिकतम तीन कृषकों के अधिकृत व्यक्ति के तौर पर काम कर सकता है तथा उपज का भुगतान पंजीकृत कृषक के बैंक खाते में किया जाएगा।

पटोरा स्टेशन के पास मिला घायल अधेड़ :गंभीर हालत में रीठी अस्पताल में एडमिट कराया

दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। कटनी-बीना रेलखंड पर स्थित पटोरा रेलवे स्टेशन के पास रविवार दोपहर एक अधेड़ गंभीर हालत में मिला। रेलवे लाइन के किनारे पड़े इस व्यक्ति को रेलवे कर्मचारियों और पुलिस की मदद से तत्काल रीठी के शासकीय अस्पताल में एडमिट कराया गया। जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब 12 बजे पटोरा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों ने इस अधेड़ को रेलवे लाइन के समीप गंभीर अवस्था में देखा। उसकी चिंताजनक हालत को देखते हुए कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायल प्रौढ़ को 108 एंबुलेंस की सहायता से रीठी के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घायल व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर उसकी शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल, उसका इलाज जारी है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।

कांसीराम के जयंती के अवसर मिशन व्यवस्था परिवर्तन द्वारा आयोजित किया गया मूलनिवासी बहुजन समता भोज

देनिक रेवांचल टाइम्स रीवा। बहुजन विचारक कांशीराम के जयंती के शुभ अवसर पर मिशन व्यवस्था परिवर्तन के टीम द्वारा मूलनिवासी बहुजन समता भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहा पर सबसे पहले अतिथियों ने भगवान बुद्ध के मूर्ति के पास कांसीराम की प्रतिमा पर भगवान बुद्ध और उनके प्रतिमा में माल्यार्पण कर नमन किया गया । जहा पर मुख्य अतिथि के रूप में यदुनाथ बौद्ध एवं विनीत विक्रम बौद्ध एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर पुष्पराज मैथोरी,बी पी नामदेव, सेवा निवृत एसडीओ जल संसाधन, रविराज बौद्ध, सरजीत साकेत ,कामता प्रसाद चौधरी मौजूद रहे। जिसकी अध्यक्षता राजेश कुशवाहा बबलु भैया द्वारा किया जिक।

इस अवसर पर राजेश कुशवाहा ने कहा कि जिस जिस तरह मुट्ठी भर लोगों ने मूलनिवासियों को जाति के टुकड़ों में बांट कर उनके ऊपर शासन की रहे है अब मूलनिवासियों को बहुजन महापुरुषों के विचार धारा के आधार पर संगठित होकर हुक्मरान बनने की जरूरत है। युवा छात्रसंघ नेता रविराज बौद्ध ने कहा कि जब तक समाज की गैर राजनैतिक जड़े मजबूत नहीं होगी तब तक मूलनिवासी बहुजन समाज शासक वर्ग नहीं बन सकता है मूलनिवासी समाज को कॉमन थाट,कॉमन ऑब्जेक्टिव,कॉमन आइडेंटिटी, के तहत यह हुक्मरान बनना पड़ेगा । इस कार्यक्रम के अंत मे मूलनिवासी बहुजन समता भोज भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राकेश यादव, राज राखन पटेल,अरुण प्रताप सिंह, डॉ नीलम सिंह, एड अरुण सिंह ,संजय कुमार साकेत, राजेश कुशवाहा,संजय कुमार साकेत, उमा शंकर बौद्ध ,शक्ति सिंह कुशवाहा, अमन कुशवाहा राजा,आर जे वर्मा,एस पी साकेत, विजय कुमार साकेत, दल प्रताप कुशवाहा, भोले रावत,अंगद साकेत, उपस्थित अन्य साथीगण मौजूद रहें।

श्रीराम कथा में प्रतिदिन हजारों की संख्या में उमड़ रही भीड़

देनिक रेवांचल टाइम्स मऊगंज। मऊगंज जिले के गन्नेशन गणेश धाम (बरॉव) में संविदाकर विजय कुमार मिश्रा के श्रेष्ठ सुपुत्र समाजसेवी इंजीनियर विनीत मिश्रा के द्वारा आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम कथा के 7वे दिन कथा व्यास स्वामी दासरथि महाराज अयोध्या धाम के मुखरबिंदो से भगवान श्रीराम के वन गवन के दौरान पिता के प्रति भक्ति और श्रद्धा का वर्णन किया गया, जिनके प्रवचन सुन श्रद्धालु जनों में श्रद्धा एवं भक्ति अनुभूति देखी गयी। कथा के माध्यम से प्रभु श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया गया। इस पावन अवसर पर पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा और आनंद का अनुभव बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह और भक्तमयी माँ गंगा प्रवाहित हो रही है ऐसा लोगों में चर्चा बनीं हुईं हैं। इस अवसर पर समाजसेवी अरविंद मिश्रा, रामहर्षण मण्डल के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती मानवती मिश्राजी, ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रतिमा मिश्रा, पूर्व नगर अध्यक्ष चंद्रप्रभा गुप्ता, भाजपा नेता त्योथर राजेन्द्र गौतम, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा, मण्डल अध्यक्ष हनुमना सुनील शुक्ला, मण्डल अध्यक्ष खरखरी मुरलीधर द्विवेदी, मण्डल अध्यक्ष मुद्रिका पटेल, भाजपा युवा नेता जवा शिवशंकर तिवारी, शानू द्विवेदी, शैलेंद्र सिंह, रवींद्रनाथ पाण्डेय, जयलाल पटेल, ओम प्रकाश तिवारी, संगमलाल पटेल, राम उजागर पटेल, कृष्णगोपाल तिवारी, मनीष गिरी, शतानंद गिरी, विनोद शुक्ल, रामायण प्यासी,बिंदेश्वरी गिरी, छोटे केवट,राजेश कुमार त्रिपाठी, परमानंद पाण्डेय, रामचरित पटेल, चंचल गिरी, अमरीश त्रिपाठी, बैजनाथ तिवारी, सौरव द्विवेदी,डीपी मिश्रा, क्षमाशंकर तिवारी, हन्ना बिमला प्रसाद द्विवेदी , सहित भक्तजन उपस्थिति रहे। धर्मप्रेमी एवं सनातन के प्रति गहरी आस्था रखने वाले वरिष्ठ संविदाकर अरविंद मिश्रा के मार्गदर्शन में यह भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हो रहा है। सच्ची निष्ठा और लगन के साथ श्रीराम कथा में अपने तन मन और धन के साथ समर्पित है इंजीनियर विनीत मिश्रा ने आप सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि आगामी दिनों में अधिक से अधिक संख्या में पधारकर रामकथा श्रवण का पुण्य लाभ प्राप्त करें और विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण करे।

शिवम भारद्वाज बने आम आदमी पार्टी शिक्षा विंग के जिलाअध्यक्ष

दैनिक रेवांचल टाइम्स रीवा। आम आदमी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से शिवम भारद्वाज को शिक्षा विंग का जिलाअध्यक्ष रीवा नियुक्त किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और सामाजिक सक्रियता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। शिवम भारद्वाज लंबे समय से शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ पार्टी ने राजेश दुबे को मुख्य विंग में जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। राजेश दुबे वर्ष 2013 से पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में लगातार योगदान दे रहे हैं। दोनों नेताओं की नियुक्ति पर प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र चौरसिया, रीवा जिलाअध्यक्ष राजीव सिंह शेरा, रवि मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा, अमित सिंह, जिला उपाध्यक्ष रवि पांडेय, नितिन तिवारी एवं राजकुमार तिवारी ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दीं। नौ दिवसीय श्रीराम कथा में 7वे दिन राम वन गवन का किया गया वर्णन।

सिलौड़ी क्षेत्र के रेता चोरों की पुलिस ने निकाली हैकड़ी, ट्रैक्टर-ट्राली जप्त

दैनिक रेवांचल टाईम्स, ढीमरखेड़ा। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में जिले में अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया एवं एस डी ओ पी महोदय स्लीमनाबाद एवं थाना प्रभारी ढीमरखेड़ा के मार्गदर्शन में चौकी सिलौडी थाना ढीमरखेड़ा पुलिस द्वारा अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। दिनांक 15.03.2026 को चौकी सिलौड़ी थाना ढीमरखेड़ा पुलिस को दतला घाट दसरमन के पास एक ट्रैक्टर-ट्राली में रेत भरे होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चालक से पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम अरविंद सोनी पिता जगदीश प्रसाद सोनी उम्र 45 साल नि. दसरमन चालक से ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस तथा ट्रैक्टर-ट्राली में भरी रेत के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, किन्तु

वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर ट्रैक्टर-ट्राली में भरी रेत को अवैध रूप से परिवहन किया जाना पाए जाने पर पुलिस द्वारा मौके पर गवाहों के समक्ष ट्रैक्टर मय एक ट्राली रेत सहित जप्त किया गया। जप्तशुदा ट्रैक्टर-ट्राली को सुरक्षार्थ चौकी परिसर में खड़ा कराया गया है तथा आरोपी के विरुद्ध धारा 106 बी.एन.एस. एस. के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी अनिल कुमार पाण्डेय , प्रधान आरक्षक अतुल शर्मा , आरक्षक रामसेवक विश्वकर्मा की विशेष भूमिका रही।

शासकीय छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, इस वर्ष पूरी तरह होगी ऑनलाइन

दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय छात्रावासों में वर्ष 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वर्ष विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष ई-हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका एवं बालक छात्रावासों में विशेष रूप से वंचित वर्ग के बालक-बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पारदर्शी ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली प्रारंभ की गई है। ई-हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली एक समेकित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया, सीट आवंटन, अभिलेख संधारण और प्रशासनिक कार्यों को ऑनलाइन एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए विकसित किया गया है। ई-हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) टाइप-क एवं टाइप-क्क्क तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस (एनएससीबी) बालक/बालिका छात्रावासों के पारदर्शी प्रबंधन और उनमें प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित की गई है। छात्रावासों में कक्षा 6वीं एवं अन्य कक्षाओं की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी प्रथम चरण में 30 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रथम चरण के बाद सीट्स रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय चरण के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। यह 06 अप्रैल 2026 से 10 जून 2026 तक चलेगी।

ढीमरखेड़ा व्यवहार न्यायालय में 52 मामलों का आपसी सहमति से हुआ निपटारा

दैनिक रेवांचल टाईम्स, ढीमरखेड़ा। शनिवार 14 मार्च 2026 को व्यवहार न्यायालय ढीमरखेड़ा परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निराकरण किया गया, जिससे न्यायालयीन प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने में सहायता मिली। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेशों के पालन में यह नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन एवं मार्गदर्शन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन

में किया गया। इस अवसर पर व्यवहार न्यायालय ढीमरखेड़ा में पदस्थ माननीय न्यायाधीश श्रीमती पूर्वी तिवारी ने न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा दीप प्रज्वलित कर प्रथम नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। लोक अदालत के दौरान कुल 52 प्रकरणों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इससे न केवल पक्षकारों को त्वरित न्याय मिला बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई। लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को सुलभ, सरल और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है, ताकि लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से लोगों को राहत मिल सके। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेश प्यासी सहित अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण शुक्ला, श्री अटल बिहारी बाजपेयी, रमेश पटेल एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे। उन्होंने लोक अदालत की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान समाज में सौहार्द और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। इस अवसर पर न्यायालय का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा और कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान किया। लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामलों में दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त करते हुए न्यायालय की इस पहल की सराहना की।

विजिट आयोजित

कटनी । मुख्यमंत्री समुदाय नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत विकासखण्ड बहोरीबंद के छात्र-छात्राओं का ग्राम अमगवा में एक्सपोजर विजिट आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने संजय लोधी की नर्सरी का अवलोकन किया। विजिट के दौरान संजय लोधी द्वारा तैयार किए गए आम एवं नींबू के बगीचे का निरीक्षण कराया गया ।

ओम होम हैल्थ केयर सर्विस
हमारे पास अशक्त बुजुर्ग मरीजों की देखभाल हेतु नर्स,वार्ड वॉय,आया बाई,फिजियोथैरेपी और दवाईयॉ घर पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
प्रो.जितेन्द्र पटैल CERVIC - 24X7 Hourse
मो. 9340721556,9753518166
पता-केनरा बैंक महाराष्ट हॉई स्कूल गोल बाजार जबलपुर(म.प्र.)

विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम संपन्न

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आज खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष नागरिक उपभोक्ता दर्शन मंच जी. पांडे, प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन श्रीमती जानकी देवी, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ. उत्तम सिंह, अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के संभागीय अध्यक्ष श्रीमती भगवती भारद्वाज, आशीष विश्वकर्मा एवं राजेंद्र कुमार जैन, राष्ट्रीय कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है और उसे कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जैसे झ सुरक्षा का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार, अपनी पसंद से वस्तु चुनने का अधिकार तथा उनके साथ कोई धोखाधड़ी होने पर शिकायत निवारण का अधिकार। कार्यक्रम में श्रीमती सीमा बोरासिया प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई कि वे एलपीजी की कमी से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। जिले में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है उन्हें किसी प्रकार की पैनिक बुकिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। नागरिकों को पीएनजी तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी गई तथा कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने उपभोक्ताओं से अपील की कि, वे वस्तु खरीदते समय बिल अवश्य लें। उत्पाद की गुणवत्ता तथा एक्सपायरी डेट की जाँच करें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कराएँ। इस अवसर पर बताया गया कि भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कन्जूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को न्याय प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। इस अवसर पर सहायक आपूर्ति अधिकारी राजधार साकेत प्रमोद मिश्रा एवं समस्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नापतौल नियंत्रक, एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और नागरिकों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

शिक्षकों का सम्मान बचाने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरूद्ध रिव्यू पिटीशन लगाने की मांग

तीस साल तक पढ़ाने वाले शिक्षक का टेस्ट लेना अनुचित

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जबलपुर ने मुख्यमंत्री म.प्र.शासन एवं मुख्य सचिव म.प्र. शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक अन्य मामले में दिए गए निर्णय की आड़ लेकर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का एक और बहाना शिक्षा विभाग के आला अफसर को मिल गया है, लोक शिक्षण संचालक भोपाल द्वारा विधि सम्मत पालन किए बगैर एक आदेश जारी किया है जिसमें 30 वर्ष की सेवा करने वाले शिक्षकों को यदि आगे नौकरी करना है तो शिक्षक पात्रता परीक्षा देना ही होगा। संचालक लोक शिक्षण के इस आदेश से शिक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मध्य प्रदेश के समस्त अध्यापक माध्यमिक शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक अपनी प्रथम नियुक्ति शिक्षा कर्मी एवं संविदा शिक्षक से होते हुए आए हैं, जो की सेवा में निरंतर है। उपरोक्त भरती न्यायालय के निर्णय के अधीन विधिवत शासन आदेश पर भर्ती नियम 1998, 2008 एवं 2018 में वर्णित सभी सेवा शर्तों में इस तरह की टी ई टी परीक्षा को उत्तीर्ण करना राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग अथवा मध्य प्रदेश शासन के किसी विभाग द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात प्रदेश के शिक्षक संवर्ग में भय एवं रोष का वातावरण बना हुआ है। संघ के अटल उपाध्याय, देवेन्द्र पचौरी आलोक अग्निहोत्री, ब्रजेश मिश्रा, रजनीश पाण्डे, मुकेश सिंह, शहजाद सिंह द्विवेदी, दालचंद पासी, गगन चौबे, प्रियांशु शुक्ला, विनय नामदेव, विवेकरंजन शुक्ला, रामशंकर शुक्ला, सुनील पचौरी, गणेश उपाध्याय, श्यामनारायण तिवारी, ममता दुबे, रीता खण्डेलवाल, सुनीता घंगोरिया, सरिता यादव, अल्का कोरी, शिखा सिह. सुनीता शुक्ला, सविता कुरील, अर्चना राजपूत, ज्योति तेलगांव, सुरेन्द्र जायसवाल, विवके जैन, दीपक सोनी, रामदास बरकड़े, शुभसंदेश सिंगौर, अंशुल साहू, बृजेश दीक्षित, अजय दुबे, सतीश उपाध्याय, राजेश चौरसिया, मनोज सिंग, प्रदीप मिश्रा, किशोर दुबे, सुरेन्द्र चौबे, जयप्रकाश गुप्ता, जे एल झारिया, प्रमोद विश्वकर्मा, बृजेश दुबे, सुरेंद्र चौधरी आदि ने माननीय मुख्यमंत्री से इस आदेश को संज्ञान में लेकर शिक्षकों को राहत दिलाने की मांग की है।

जबलपुर में दो जगहों पर निकले सांप, घरों में मची अफरा-तफरी

सर्प विशेषज्ञ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू, दोनों सांपों को जंगल में छोड़ा

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। शहर के गढ़ा थाना क्षेत्र और विजय नगर इलाके में अलग-अलग स्थानों पर सांप निकलने से हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर सर्प विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और दोनों सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक आईजी कार्यालय में पदस्थ निरीक्षक कुंडल चौधरी के आनंद कुंज स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी के घर में दोपहर करीब एक बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब उनके कमरे में करीब चार फीट लंबा सांप घुस गया। कमरे में सांप दिखाई देने पर परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत सर्प विशेषज्ञ को सूचना दी। सूचना मिलने पर सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया। बताया गया कि पकड़ा गया सांप कीलबैक चेकर्ड पनिहिया प्रजाति का था, जो जहरीला नहीं होता। बाद में उसे देवताल तालाब क्षेत्र के जंगल में छोड़ दिया गया।

विजय नगर में मिला छह फीट लंबा सांप

इसी तरह विजय नगर क्षेत्र में रहने वाले आरके खरे ने शाम को सूचना दी कि उनके घर के मुख्य गेट पर करीब छह फीट लंबा सांप लिपटा हुआ है। सूचना पर सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। बताया गया कि खरे के घर से पकड़ा गया सांप धामन प्रजाति का था, जो जहरीला नहीं होता। रेस्क्यू के बाद उसे भी सुरक्षित स्थान पर जंगल में छोड़ दिया गया। सर्प विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि घर या आसपास कहीं सांप दिखाई देने पर घबराएं नहीं और उसे पकड़ने की कोशिश न करें। तुरंत विशेषज्ञों को सूचना दें, ताकि सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके।

बेटे के पहले जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं, डीजे बंद कराने के विवाद के बाद युवक ने लगाई फांसी

रात में डीजे बजाने को लेकर परिवार से हुआ विवाद, नशे की हालत में कमरे में जाकर उठाया आत्मघाती कदम

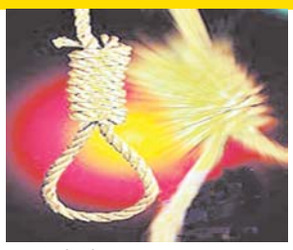

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। बेटे के पहले जन्मदिन की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब डीजे बंद कराने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मझगवां थाना क्षेत्र में रहने वाले राजेंद्र रजक ने पुलिस को बताया कि उसके बड़े बेटे प्रिंस रजक (22) के बच्चे का पहला जन्मदिन था। इस अवसर पर घर में परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ जन्मदिन का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाकर नाच-गाना चल रहा था और सभी लोग खुशी मना रहे थे।

कमरे में जाकर लगा ली फांसी

रात करीब 3 से 3:30 बजे के बीच प्रिंस अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद छोटे भाई ने दरवाजा खोला तो देखा कि प्रिंस ने पंखे से चुन्नी के सहारे फांसी लगा ली है। परिजन तुरंत उसे फंदे से उतारकर सिहोरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में डीजे बंद कराने को लेकर हुए विवाद के बाद युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आई है। बताया गया कि रात करीब 11 बजे आसपास के लोगों ने तेज आवाज में डीजे बजने पर आपत्ति जताई। इसके बाद परिवार के लोगों ने प्रिंस से डीजे बंद कराने के लिए कहा। इस बात को लेकर घर में कहासुनी हो गई। कुछ देर बाद प्रिंस बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया। करीब दो घंटे बाद वह शराब पीकर वापस घर लौटा और परिवार के सदस्यों से डीजे बंद कराने की बात को लेकर विवाद करने लगा। परिवार के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए डीजे बंद कराया गया।

अवैध एलपीजी गैस सिलेंडर व रेत पर की कार्यवाही

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निदेशों के परिपालन में आज अनुभागीय राजस्व अधिकारी शहपुरा और पुलिस विभाग द्वारा शहपुरा में एलपीजी गैस सिलेंडर की अवैध उपयोग की जांच की गई। जांच के दौरान 10 अलग-अलग प्रतिष्ठानों से 10 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी शहपुरा के मार्गदर्शन में तहसील शहपुरा में एक रेत से भरा डम्फर जब्त कर थाना चरगवां भेजा गया। ड्राइवर के कथन से तथ्यों का मिलान न होने के कारण आवश्यक कार्यवाही की गई। कार्यवाही के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

होलीका दहन के चंदे को लेकर विवाद, मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। होलीका दहन के लिए मोहल्ले में चंदा वसूली को लेकर हुए विवाद में मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा बढ़ाते हुए फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रांझी थाना पुलिस के अनुसार 1 मार्च को 19 वर्षीय मनीष रैकवार अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में होली के लिए चंदा एकत्र कर रहा था। इसी दौरान क्षेत्र में रहने वाले कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया। बताया गया कि विवाद के दौरान आरोपियों ने मनीष पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आ गई। घटना के बाद परिजनों ने उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी हालत लगातार गंभीर बनी रही। सिर में गंभीर चोट होने के कारण आखिरकार मनीष रैकवार ने दम तोड़ दिया।

नवरात्रि में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, शहर में शांति बनाए रखने का लक्ष्य

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। नवरात्रि के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने शहरभर में विशेष इंतजाम किए हैं। थाना क्षेत्रों में फिक्स प्वाइंट्स पर पुलिस बल तैनात किया गया है और रात्रि गश्त को सुनिश्चित किया जाएगा। थाना प्रभारी और संभागीय अधिकारी सभी स्थानों पर नजर बनाए रखेंगे, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही न हो और आम जनता को पूरी सुरक्षा का एहसास हो। नवरात्रि के दौरान महिलाएं और बच्चे सुबह से लेकर देर रात तक सड़कों पर होते हैं, खासकर मंदिरों के दर्शन के लिए। ऐसे में पुलिस बल को प्रमुख सड़कों पर तैनात किया गया है। सूनसान मार्गों और कॉलोनियों में पुलिस वाहनों द्वारा लगातार गश्त की जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। थाना प्रभारी मंदिर समितियों के सदस्य और वालेंटियरों से लगातार संपर्क बनाए रखेंगे, ताकि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति से निपटा जा सके।

महिला पुलिस बल की तैनाती

शहर के प्रमुख मंदिरों के पास महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। खासकर उन मंदिरों के पास जहाँ जल लेकर जाने वाली महिलाएं और युवतियां होती हैं, जैसे बड़ी खेरमाई, छोटी देवन, बंग्लामुखी मंदिर, शीतलामाई और शारदा माता मंदिर। इन स्थानों पर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महिला पुलिस को तैनात किया जाएगा, ताकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सीसीटीवी के जरिए निगरानी

नवरात्रि के नौ दिनों तक चिन्हित भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन अपनी 'तीसरी आंख' यानी सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखेगा। 24 घंटे पुलिस कंट्रोल रूम में 2 से 3 अधिकारी इन कैमरों के फुटेज पर निगरानी रखेंगे। साथ ही, भीड़ में सादे लिबास में पुलिस कर्मी चोरों और जेबकतरों पर नजर बनाए रखेंगे। किसी भी विवाद या झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस को 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

गलत पार्किंग पर चालानी कार्रवाई

मंदिरों के पास गलत पार्किंग पर भी इस बार पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मंदिरों के आसपास वाहनों के गलत तरीके से खड़े होने पर यातायात पुलिस चालानी कार्रवाई करेगी। खासकर बड़े मंदिरों के पास लोडिंग वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मंदिरों के आसपास जाम की स्थिति पर भी नजर रखेंगी, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। कॉलोनियों और दुर्गा मंदिरों के आसपास पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए मंदिर समिति के साथ थाना पुलिस चर्चा कर रही है।

एसपी का निर्देश

एसपी सम्पत उपाध्याय ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी मंदिर के पास जाम की स्थिति नहीं बनने पाए। जाम लगने की स्थिति में पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। इस प्रकार, पुलिस प्रशासन ने नवरात्रि के दौरान शहर में शांति बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है।

जैविक हाट में लोगों ने की पसंद के उत्पादों की खरीदारी

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। जैविक खेती कर रहे किसानों के उत्पादों के विक्रय के लिये इस रविवार को भी कृषि उपज मंडी जैविक हाट लगाया गया। जैविक हाट में किसानों द्वारा जैविक तरीके से उत्पादित अनाज, दालें, सब्जियाँ, मसाले एवं अन्य कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया तथा बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पहुँचकर पसंद के उत्पादों की खरीदारी की। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा लगाये गये जैविक हाट में कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को जैविक खेती की उन्नत तकनीकों, जैविक खाद के उपयोग तथा जैविक प्रमाणन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर अधिकारियों ने किसानों को अधिक से अधिक क्षेत्र में जैविक खेती अपनाने की अपील की जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों ने जैविक उत्पादों के महत्व को समझते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्रीमती प्रतिभा गौर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पंकज शर्मा सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही बड़ी संख्या में किसान, उपभोक्ता प्रतिभागी के रूप में उपस्थित रहे।

म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद के आगामी चुनाव वर्ष 2026 में सदस्य पद हेतु आपकी
प्रथम वरीयता मत का आकांक्षी
गोपाल सिंह बघेल (अधिवक्ता)

म.प्र. उच्चन्यायालय
जबलपुर (म.प्र.)
पता - हॉल नं 3 सीट नं 7 विधि भवन, म.प्र.
उच्चन्यायालय जबलपुर (म.प्र.)
कार्यालय-निवास
कृष्णा कॉलोनी के पास राज
परिसर सुहागी, जबलपुर (म.प्र.)
Mob.: 9229653295, 8989141208, 7987512717

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, मुकेश कुमार श्रीवास द्वारा माँ रेवा पब्लिकेशन एन्ड प्रिंटर्स लष्मीपुर मुस्कान प्लाजा के पीछे विवेकानंद वार्ड एम आर 4 रोड़ जबलपुर म.प्र. 482001 से मुद्रित तथा लष्मीपुर मुस्कान प्लाजा के पीछे एम आर 4 रोड 21 स्वामी विवेकानंद वार्ड जबलपुर म.प्र. 482001 से प्रकाशित । संपादकः अतुल कुमार बंदेवार RNI. Reg. No MPHIN/2023/90965 (समस्त विवादों का न्यायालयीन क्षेत्र जबलपुर) Email:- revanchaljabalpur@gmail.com मोब. 7509202320, 9406771592